हिंदी दैनिक

कलम की पहल

PRGI NO. UAHIN/25/A1323

वर्ष : 02 अंक : 151 पृष्ठ : 08 मूल्य : 1 रूपए नैनीताल, गुरूवार, 19 नवंबर, 2026

E-mail: kalamkipahaluk@gmail.com Website: kalamkipahal.com

नशे की समस्या का जिक्र कर जब भावुक हो गए पीएम मोदी

जब नक्सलवाद खत्म हो सकता है तो ये क्यों नहीं...

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में नशे की बढ़ती समस्या पर गहरी चिंता जताई. नशे पर बात करते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए. उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से बचाना देश की बड़ी जिम्मेदारी है और इस समस्या को जड़ से खत्म करना होगा. प्रधानमंत्री ने कहा, 'जब नक्सलवाद खत्म हो सकता है तो नशे की समस्या भी खत्म हो सकती है.' उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा एजेंसियों और सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि नक्सलवाद की दोबारा वापसी न हो.

बैठक में प्रधानमंत्री ने देश में गरीबी कम होने पर भी चर्चा की.



उन्होंने कहा, 'जब 2014 में सरकार बनी थी तब सेंट्रल हॉल में मैंने कहा था कि सरकार गरीबों के लिए है.' उन्होंने बताया कि आज 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल चुके हैं. प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि यह उपलब्धि कायम रहनी चाहिए और जो लोग गरीबी से बाहर आए हैं वे दोबारा गरीबी में न जाएं.

प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को बचत पर विशेष ध्यान देना होगा. उन्होंने कहा कि भारतीय समाज की पहचान बचत की आदत है. 'ईट ड्रिंक एंड मेरी पर विश्वास नहीं करते भारतीय.' उन्होंने आर्थिक सुरक्षा और वित्तीय सशक्तीकरण को भविष्य की बड़ी आवश्यकता बताया.

करीब साढ़े तीन घंटे चली मंत्रिपरिषद की बैठक में तीन महत्वपूर्ण प्रजेंटेशन दिए गए. एक प्रस्तुति 50 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने की उपलब्धि पर केंद्रित थी. इसमें विश्व बैंक की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया गया. वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, मत्स्य पालन समेत 11 मंत्रालयों और विभागों के सचिवों ने बताया कि किस तरह केंद्र सरकार की योजनाओं ने गरीब परिवारों की जिंदगी बदली है.

प्रस्तुति में प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर जल योजना, उज्ज्वला योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT), डिजिटल पहुंच और बैंकिंग सुविधाओं का उल्लेख किया गया. बताया गया कि इन पहलों ने करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर आने में मदद की.

बैठक में देश को नक्सल मुक्त बनाने के प्रयासों और जनधन योजना के जरिए वित्तीय सशक्तीकरण पर भी प्रस्तुति दी गई. सितंबर में हुई चिंतन बैठक में तय लक्ष्यों और सुधारों की प्रगति की समीक्षा भी की गई. आसियान बैठक से देर रात लौटने के बाद प्रधानमंत्री बुधवार सुबह सीधे भारत मंडपम पहुंचे और बैठक में हिस्सा लिया.

'मुझसे मुकाबला करना है तो चलना होगा 4000KM पैदल'; चैलेंज दे पीएम मोदी की राहुल गांधी ने की तारीफ भी



नई दिल्ली। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर से केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आए हुए हैं। दरअसल, उन्होंने न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में कहा है कि भारत गंभीर आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा है और देश में भारी बेरोजगारी है। इसके साथ ही इसी मंच से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने से (राहुल से) मुकाबला करने के लिए एक बड़ी चुनौती दे डाली। राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा, 'अगर आप मुझसे मुकाबला करना चाहते हैं, तो आपको 4,000 किलोमीटर पैदल चलना होगा। लेकिन अगर आप 4,000 किलोमीटर पैदल चलते हैं, तो लोग कहेंगे कि आप मेरी नकल कर रहे हैं। दरअसल, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आयोजित एक खुले संवाद कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने अपनी 4,000 किलोमीटर लंबी 'भारत जोड़ो यात्रा', अपनी राजनीतिक पहचान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक शैली पर बेबाक राय रखी। उन्होंने अपनी 4,000 किलोमीटर लंबी 'भारत जोड़ो यात्रा' का जिक्र करते हुए राजनीतिक विशिष्टता (यूनिकनेस) के विचार को समझाया। इसके साथ ही राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की और उन्हें एक ऐसे राजनेता के तौर पर पेश किया, जिन्होंने भारतीय राजनीति में अपनी एक अलग और खास पहचान बनाई है। हालांकि, गांधी ने कहा कि अगर कोई उनसे इस 'यात्रा' के मोर्चे पर मुकाबला करना चाहता है, तो उसे भी ऐसी ही यात्रा करनी होगी, बल्कि उससे भी लंबी यात्रा करनी होगी। अन्यथा लोग उस यात्रा को मेरी नकल कहेंगे।

उन्होंने कहा, 'एक राजनेता के तौर पर मोदी भी असल में इससे मुकाबला नहीं कर सकते लेकिन आप सोचें, तो वे अन्य सभी राजनेताओं से बुनियादी तौर पर अलग हैं।' अपने भांजे के साथ हुई बातचीत का जिक्र करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि अगर आप सिर्फ प्रतिस्पर्धा (मुकाबला) कर रहे हैं, तो आप पहले ही पिछड़ चुके हैं; असली सफलता इसमें है कि आप बिना रुके कुछ अलग करते रहें ताकि बाकी लोग अपने आप पीछे छूट जाएं।

चीन पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन से मिलाया हाथ, देखते रहे पास खड़े शी जिनपिंग



नई दिल्ली। चीन में इस समय APEC देशों का जमावड़ा लगा हुआ है। पूरी दुनिया की नजर लेकिन इस मीटिंग से ज्यादा ट्रंप, पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात पर है। बुधवार को समूह के फोटो सेशन के दौरान भी एक ऐसा ही घटनाक्रम देखने को मिला। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक जगह पर खड़े होकर बाकी नेताओं का स्वागत कर रहे थे। वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के पहुंचने के बाद दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया। इसके बाद वहां पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी पहुंचे। पुतिन ने सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिलाया। इसके बाद तीनों नेताओं के बीच अभिवादन का एक दौर शुरू हो गया। एशिया-पैसिफिक इकॉनॉमिक कॉर्पोरेशन (APEC) समूह के शिखर सम्मेलन के दौरान तीनों नेताओं के बीच होने वाली इस बैठक पर पूरी दुनिया की नजर है। तीनों नेताओं ने इस हल्की बातचीत के बाद समूह के बाकी नेताओं के साथ फोटो भी खिंचवाई। इस दौरान मेजबान के तौर पर चीनी राष्ट्रपति शी और उनकी पत्नी पेंग मध्य में रहे। उनके पास में ही पुतिन और ट्रंप भी मौजूद थे।

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ा, 1 दिसंबर से होगा लागू

चम्पावत। प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं के परिश्रम और सेवाभाव को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके मानदेय में वृद्धि की है।



इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। बढ़ा हुआ मानदेय 1 दिसंबर 2026 से लागू होगा। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां और सहायिकाएं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, बाल पोषण और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती हैं। मानदेय वृद्धि को उनके योगदान के सम्मान और आर्थिक मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस निर्णय से आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं में खुशी का माहौल है।

जालंधर में राहुल पर नितिन नवीन का बड़ा हमला

टूलकिट बनकर अराजतकता फैलाना चाहते

जालंधर। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने बुधवार को जालंधर में 'समरसता संकल्प यात्रा' को हरी झंडी दिखाई. इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'जब देश विकास कर रहा है, तब राहुल गांधी को आपदा दिखाई दे रही है. आप टूल किट बनकर अराजकता फैलाना चाहते हैं, लेकिन आप अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे. बीजेपी अध्यक्ष ने पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधते हुए कहा कि नशा के जरिए आपने यहां की जवानी को भटकाने का काम किया है. आपने जो नशा मुक्ति का वादा किया था वो पूरा नहीं किया है. वो केवल आपके लिए राजनीति का मुद्दा बनकर रह गया है. जिस दिन हमारी सरकार पंजाब में बनेगी, हम पंजाब को नशा मुक्ति के लिए लगातार काम करेंगे. नवीन ने पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा, 'यहां कानून केवल अरविंद केजरीवाल की जेब भरने के लिए है और उनका एटीएम कराकर रख दिया है. मौजूदा सरकार ने केवल पंजाब के महिलाओं, किसानों , युवाओं को ठगने का काम किया है. पंजाब के युवाओं को बेरजोगार कर दिया है और अब उसने से एक करोड़ युवा ढूंढ़ रहे हैं और उसके लिए पंजाब द करोड़पति करके योजना ला रहे हैं. पंजाब के पास पैसा नहीं है और वो केवल भरमाने का काम कर रहे हैं और वेलफेयर की स्कीम की बात कर रहे हैं. श्री गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के मौके पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन 18 नवंबर को जालंधर से पार्टी की 'समरसता संकल्प यात्रा' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह यात्रा 2,558 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और इसकी शुरुआत जालंधर-पठानकोट राजमार्ग पर डेरा सचखंड बल्लान के पास रायपुर गांव से होगी.



हिमाचल के मंडी में दर्दनाक हादसा, 200 फीट गहरी खाई में गिरी कार, 6 की मौत

मंडी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के लडभड़ोल में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में छह युवकों की मौत हो गई. हादसा लडभड़ोल बाजार में पेट्रोल पंप के समीप पेश आया, जहां एक कार अनियंत्रित होकर करीब 200 फुट गहरी खाई में जा गिरी. दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार सभी छह लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. जानकारी के अनुसार, कार में सवार सभी युवक आसपास के गांवों के स्थानीय निवासी बताए जा रहे हैं. हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई. आसपास



मौजूद स्थानीय लोग तुरंत राहत एवं बचाव कार्य के लिए मौके पर पहुंचे. लोगों ने खाई में उतरकर कार सवारों को बाहर निकालने और उनकी जान बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक सभी छह युवकों की मौत हो चुकी थी. घटना की सूचना मिलते ही लडभड़ोल पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद सभी शवों को खाई से बाहर निकाला. एक ही हादसे में छह युवकों की मौत से लडभड़ोल और आसपास के क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ गई है. हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है.

बता दें कि यह हादसा रात मे हुआ और इसका पता अगले दिन लगा. हादसे में जान गंवाने वाले लोगों में कुछ नाबालिग भी शामिल हैं. इस घटना की जानकारी एक युवक द्वारा खाई में गिरी कार देखने के बाद मिली. युवक की जानकारी पर रेस्क्यू अभियान चलाया गया. बताया जा रहा है कि युवक करीब 15 घंटे से लापता थे.

लश्कर कमांडर लतीफ भट का खेल खत्म, सुरक्षाबलों ने कर दिया ढेर

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में आठ दिनों से जारी सघन अभियान में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का वांछित कमांडर लतीफ भट मुठभेड़ में मार गिराया गया है। लतीफ ही 11 नवंबर को हुए सीआरपीएफ चौकी हमले का मास्टरमाइंड था, जिसमें तीन जवान घायल हुए थे। सुरक्षाबलों ने लतीफ भट का एनकाउंटर करके हमले का बदला ले लिया है। सुरक्षाबलों को सूचना मिली थी कि लतीफ कुलगाम की एक मस्जिद में छिपा हुआ है। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षाबलों ने विशेष संयम बरता ताकि मस्जिद को कोई नुकसान न पहुंचे। इसके बाद लतीफ को आत्मसमर्पण के लिए वीडियो कॉल के माध्यम से अंतिम मौका दिया गया, लेकिन आंतकी लतीफ ने इंकार कर दिया। इसके बाद, सुरक्षाबलों ने आंतकी को बाहर निकालने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए, जिसमें से कुछ मस्जिद के अंदर भी गिरे। जैसे ही लतीफ मस्जिद से बाहर निकला, परिसर के बाहर सुरक्षाबलों ने तभी ढेर कर दिया।

लतीफ ने अपने साथी उमर निसार डार के साथ मिलकर 11 नवंबर को अखरान (मीर बाजार के पास) स्थित सीआरपीएफ चौकी पर हमला किया था, जिसमें तीन जवान घायल हुए थे। इस हमले के तुरंत बाद सुरक्षाबलों ने तलाशी अभियान शुरू किया था। पिछले आठ दिनों से पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी थी, जहां करीब 600 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ की गई और कई को आधिकारिक तौर पर हिरासत में भी लिया गया। घेराबंदी वाले इलाकों में आने-जाने के सभी रास्तों पर कई स्तरों के चेकपॉइंट बनाए गए थे। बता दें कि 16 नवंबर को भी लतीफ को कुलगाम के लारू इलाके में घेरा गया था, लेकिन वह मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा घेरा तोड़कर भागने में सफल रहा था। हालांकि, उस मुठभेड़ में उसका साथी उमर निसार डार मारा गया था।



मुंबई में दाऊद इब्राहिम के 'हेडक्वार्टर' को ढहाए जाने पर बवाल, 'मुसाफिरखाने' को मस्जिद बताकर विरोध में उतरे लोग

मुंबई। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भिंडी बाजार स्थित 'मुसाफिरखाना'- 'हाजी इस्माइल हबीब मुसाफिरखाना' 80 साल से भी अधिक पुरानी और जर्जर इमारत है, जिसे दाऊद इब्राहिम का घर और उसके अवैध धंधों का हेडक्वार्टर भी माना जाता था. 1980 के दशक तक ये इलाका दाऊद इब्राहिम और उसके गिरोह के शुरुआती ठिकाने या अड्डे के रूप में जाना जाता था. बताया तो ये भी जाता है कि दाऊद के अवैध धंधे और स्मगलिंग का सामान यहीं स्टोर होता था.1986



में देश छोड़ने से पहले दाऊद और उसका परिवार इसी मुसाफिरखाना इमारत की दूसरी मंजिल पर रहता था. यहीं उसका दफ्तर भी था, जहां 1993 मुंबई हम धमाकों की साजिश रची गई थी.यहां कास्कर परिवार जिसमें दाऊद इब्राहिम और उसके भाई बहन उसके देश छोड़ने से पहले तक रहे.दाऊद के जाने के बाद उसकी मां अमीना बी वहीं रहीं, बाद के सालों में उसके भाई इकबाल कास्कर इमारत को इस्तेमाल करने और फ्लैटों और दुकानों में किरायेदारों के रहने की खबरें आती रहीं.पूरी इमारत में ग्राउंड फ्लोर पर कुल 32 व्यावसायिक दुकानें और ऊपर 19 आवासीय कमरे थे.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने साल 2020 में इस जर्जर इमारत को पहली और दूसरी मंजिल गिराने का आदेश दिया था, इसके बाद बीएमसी ने इमारत को खाली कराने और गिराने की प्रक्रिया शुरू की थी. पिछले कुछ वर्षों में इमारत के ऊपरी हिस्सों और आवासीय कमरों को खाली करवाकर आंशिक रूप से तोड़ा जा चुका है. ये इमारत बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुकी थी. दाऊद के इस्तेमाल वाले मुख्य कमरे हाल के सालों में तोड़े जा चुके हैं, अब ग्राउंड फ्लोर पर प्रेयर हॉल और पहली मंजिले पर करीब 10 कमरे बचे हैं.

आजम खान जेल से हुए रिहा, डासना जेल के बाहर भारी संख्या में मौजूद समर्थकों ने किया स्वागत

गाजियाबाद। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा हो गए हैं.गाजियाबाद की सीजेएम कोर्ट में बुधवार को उनकी जमानत से जुड़ी सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद उनकी रिहाई हुई है. कोर्ट ने जमानत के लिए 50-50 हजार रुपये के दो जमानती और 50 हजार रुपये के निजी मुचलके की शर्त रखी थी. इस मामले में शहनवाज और जुनैद जमानती बने. दोनों की ओर से 50-50 हजार रुपये की एफडी भी जमा कराई गई. इसके साथ ही अदालत के निर्देश के अनुसार एक एफिडेविट भी दाखिल किया गया. आजम खान के वकीलों ने जमानत से जुड़ी सभी जरूरी कानूनी औपचारिकताएं समय पर पूरी कर दीं, जिसके बाद उनकी अब रिहाई हो गई है .



आल्माकोटेज मार्ग जो आपदा की भेंट चढ़ गया। जिसका अभी तक निर्माण कार्य सुचारू न होने पर शिष्टमंडल ने देहरादून अधिकारियों से वार्ता कर ज्ञापन सौंपा

के.के.पी संवाददाता

नैनीताल। सरोवर नगरी आल्माकोटेज के पास विगत एक वर्ष से अधिक का समय हो गया जो कि आपदा के दौरान भूस्खलन के चलते सड़क मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था जो अभी तक नही बन पाया है। इधर क्षेत्र वासियों ने हो हल्ला कर विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किये जाने की बात भी कह डाली है। यहाँ बता दें पूर्व 2022 में भी यह मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। जिसमें क्षेत्र वासियों ने नारा दिया था रोड नही तो वोट नहीं उस समय आनन फानन में सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया था और आवाजाही इस मार्ग से शुरू हो गई थी। विगत 2025 की आपदा में यह आल्माकोटेज मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। और आवाजाही पूर्ण रूप से बन्द हो गई। फिर क्षेत्र वासियों ने मन बना



डाला है अगर मार्ग निर्माण विधानसभा चुनाव से पहले शुरू नही होता है तो चुनाव के बहिष्कार करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। स्नोव्यू वार्ड 5 के सभासद जितेंद्र कुमार पांडे जीनू ने लगातार आल्माकोटेज मार्ग के निर्माण के लिए प्रयास करते हुए आ रहे हैं। अभी देहरादून अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश चन्द्र, एवं निदेशक यू एल एम एम सी शांतनु सरकार से मुलाकात कर वस्तु स्थिति से अवगत कराया जिस पर अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया है शीघ्र मार्ग निर्माण कार्य सुचारू रूप से कर दिया जायेगा। इससे पूर्व नगर पालिका सभासद जितेंद्र कुमार पांडे,जीनू, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश जोशी मंटू,पूर्व नगर पालिका सभासद दीपक कुमार भोलू एवं अवकाश प्राप्त शिक्षक व सामाजिक कार्यकर्ता खुशाल सिंह रावत ने कुमाऊँ आयुक्त मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत, क्षेत्रीय विधायक सरिता आर्या, नैनीताल सांसद अजय भट्ट, जिला अधिकारी ललित मोहन रयाल से भी मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है पर अभी तक कोई भी ठोस कार्यवाही अमल में नही लाई गई है। इसी क्रम में देहरादून भी अधिकारियों से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया है। जिसमें आश्वासन दिया गया है कि शीघ्र समस्या का निराकरण किया जायेगा अब यह देखना है कि कब तक आल्माकोटेज मार्ग का निर्माण सुचारू रूप से किया जायेगा।

जबकि तमाम आला अधिकारी इस मार्ग का निरीक्षण कर चुके हैं। नव सांस्कृतिक सत्संग समिति शेर का डांडा रामलीला मंचन के दौरान तो विधायक सरिता आर्या ने क्षेत्र वासियों को आश्वासन दिया कि सरकार द्वारा धनराशि निर्माण कार्य हेतु मुहैया करा दी गई है।

भावना मेहरा ने बाबियाड़, दुदली, कालगड़ी व चूरीगाड़ का किया दौरा, जनसमस्याएं सुन मौके से अधिकारियों को दिए निर्देश

के.के.पी संवाददाता

भीमताल। उत्तराखंड आवास सलाहकार परिषद की उपाध्यक्ष (राज्यमंत्री) भावना मेहरा ने बुधवार को भीमताल विधानसभा के बाबियाड़ दुदली, कालगड़ी एवं चूरीगाड़ क्षेत्रों का भ्रमण कर ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं एवं क्षेत्रीय आवश्यकताओं की जानकारी ली इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लिए जा रहे जनहितकारी निर्णयों की जानकारी भी दी भ्रमण के दौरान बाबियाड़ पहुंचने पर ग्रामीणों ने सड़क निर्माण एवं सड़क के क्षतिग्रस्त होने की समस्या प्रमुखता से उठाई जिसपर पर भावना मेहरा ने तत्काल मौके से ही लोक निर्माण विभाग के



अधिकारियों को फोन कर समस्या के समाधान के निर्देश अधिकारियों को दिए अधिकारियों ने उन्हें आश्वस्त किया कि एक माह के भीतर सड़क को ठीक करने के साथ ही निर्माण कार्य प्रारंभ करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी इस दौरान बाबियाड़ में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए भावना मेहरा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सरकार द्वारा आशा कार्यकर्ताओं एवं भोजन माताओं के मानदेय में वृद्धि सहित महिलाओं युवाओं किसानों और जरूरतमंद परिवारों के हित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना और ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना है उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि क्षेत्र की समस्याओं को संबंधित विभागों के समक्ष उठाकर उनके समाधान के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर विकास कार्यों को गति देना उनकी प्राथमिकता में है इस दौरान ग्राम प्रधान सुनील कुमार पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट, पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख कृपाल मेहता शिवराम चंदन सम्मल ओमप्रकाश सिंह, धर्मेंद्र सिंह भवान सिंह रमेश मेहता चंदन लाल शेर सिंह मेहता पान सिंह मेहता मनोज सिंह मेहता त्रिलोक मेहता गिरीश शर्मा चेतन शर्मा कमल कोटलिया एवं मोहन शर्मा सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे।

एक नजर

विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 की तैयारियों के तहत जनपद बागेश्वर में बुधवार से ईवीएम एवं वीवीपैट प्रशिक्षण तथा जन-जागरूकता अभियान शुरू हो गया है



के.के.पी संवाददाता। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अपूर्वा पाण्डे ने भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप जनपद के दोनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर अभियान संचालित करने के निर्देश दिए हैं। यह अभियान 18 नवंबर से निर्वाचन की घोषणा होने तक जारी रहेगा।

अभियान के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय एवं विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालयों में ईवीएम प्रदर्शन केंद्र स्थापित किए गये है। इसके साथ ही विधानसभा क्षेत्रों के समस्त मतदेय स्थलों पर मोबाइल डेमोंस्ट्रेशन वैन के माध्यम से ईवीएम एवं वीवीपैट के संचालन और कार्यप्रणाली की जानकारी दी जा रही है। सभी प्रदर्शन केंद्रों एवं मोबाइल वैन के माध्यम से प्रतिदिन प्रातः 09 बजे से सायं 05 बजे तक प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनरों द्वारा ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों की कार्यप्रणाली का व्यावहारिक प्रदर्शन कर मतदाताओं की जिज्ञासाओं का समाधान किया जाएगा।

दुर्गम बेलवाल गांव 8 किमी पैदल पहुंची धौलछीना पुलिस, ग्रामीणों के बीच लगाया थाना दिवस

के.के.पी संवाददाता/अल्मोड़ा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोडके के निर्देश पर मंगलवार को थाना धौलछीना पुलिस दुर्गम बेलवाल गांव में करीब 7-8 किलोमीटर पैदल पहुंची और ग्रामीणों के बीच थाना दिवस का आयोजन किया। इस दौरान थानाध्यक्ष रमेश बोरा ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और विभिन्न अपराधों से बचाव तथा सुरक्षा के संबंध में आवश्यक जानकारी दी। पुलिस टीम ने ग्रामीणों को डिजिटल अरेस्ट, क्यूआर कोड स्कैम, ओटीपी फ्रॉड, एटीएम धोखाधड़ी, फिशिंग और अनजान लिंक के माध्यम से होने वाली साइबर ठगी के तरीकों की जानकारी दी। ग्रामीणों से अनजान कॉल, संदिग्ध लिंक और फर्जी वेबसाइट से सावधान रहने तथा ओटीपी एवं बैंकिंग से जुड़ी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करने की अपील की गई। सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग करने और मजबूत पासवर्ड रखने के लिए भी प्रेरित किया गया। साइबर ठगी होने पर तत्काल 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने की जानकारी दी गई। ग्रामीणों को महिला एवं बाल अपराध, बाल विवाह और नशे के दुष्परिणामों के बारे में भी जागरूक किया गया। पुलिस ने किसी भी प्रकार के शोषण या अपराध की स्थिति में चुप न रहने और तत्काल पुलिस को सूचना देने की अपील की। आपातकालीन पुलिस सहायता के लिए डायल 112 की जानकारी भी दी गई। इस दौरान गांव में ग्राम सुरक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया और ग्रामीणों को गांव की सुरक्षा तथा अपराधों की रोकथाम में पुलिस का सहयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। पुलिस टीम ने गांव में रहने वाले 92 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक गोपाल सिंह मलवाल तथा पुलिस विभाग में नियुक्त एक कर्मचारी की माताजी से भी मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना और उनकी समस्याओं की जानकारी ली।

हल्द्वानी दुष्कर्म मामले को लेकर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने किया प्रदर्शन

के.के.पी संवाददाता/अल्मोड़ा। उत्तराखंड में महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ यौन हिंसा की बढ़ती घटनाओं को लेकर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने आक्रोश जताते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतला दहन किया। समिति ने हल्द्वानी में नाबालिग के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना को गंभीर बताते हुए मामले में गिरफ्तार चारों आरोपियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की मांग की। बुधवार को संगठन से जुड़े लोग चौघानपाटा पर एकत्र हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राज्य अध्यक्ष सुनीता पांडे ने कहा कि उत्तराखंड की जनता अंकिता भंडारी मामले में न्याय और कथित वीआईपी को कठघरे में लाने की मांग को लेकर संघर्ष कर रही है। इसी बीच हल्द्वानी में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आना बेहद गंभीर और चिंताजनक है। समिति ने आरोप लगाया कि घटना के मुख्य आरोपी धीरज बिष्ट का संबंध भाजपा की छात्र इकाई एबीवीपी से रहा है और वह पूर्व में छात्रसंघ अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ चुका है। समिति ने कहा कि महिलाओं और बेटियों के खिलाफ होने वाली यौन हिंसा की घटनाओं में किसी भी प्रकार का राजनीतिक संरक्षण या दबाव स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। समिति ने हल्द्वानी मामले में गिरफ्तार धीरज बिष्ट, अंश खत्री, नितिन पाल और हिमांशु गौनी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की।

कुसेरी-सिलोनी मोटर मार्ग के हॉटमिक्स डामरीकरण को शासन से मिली स्वीकृति, क्षेत्रवासियों को मिलेगा लाभ

जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगांई ने संबंधित विभाग को शीघ्र कार्य प्रारंभ करने के दिए निर्देश

के.के.पी संवाददाता

पिथौरागढ़, जनपद के मूनाकोट विकासखंड अंतर्गत कुसेरी से सिलोनी मोटर मार्ग के सुधारीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है। मार्ग के हॉटमिक्स डामरीकरण कार्य के लिए शासन द्वारा राज्य योजना के तहत 199.17 लाख रुपये (एक करोड़ 99 लाख 17 हजार रुपये) के आगणन को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ के प्रांतीय खंड के अंतर्गत आने वाले इस मोटर मार्ग के सुधारीकरण एवं हॉटमिक्स डामरीकरण से क्षेत्र के लोगों को आवागमन में बेहतर सुविधा मिलेगी। सड़क की स्थिति में सुधार होने से स्थानीय ग्रामीणों को सुगम एवं सुरक्षित यातायात की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।



जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगांई ने कहा कि कुसेरी-सिलोनी मोटर मार्ग के सुधारीकरण से क्षेत्रीय जनता को लाभ मिलेगा तथा आवागमन और अधिक सुगम होगा। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वीकृति के उपरांत अग्रिम कार्यवाही में किसी भी प्रकार का विलंब न किया जाए। सभी आवश्यक प्रक्रियाएं समयबद्ध ढंग से पूर्ण करते हुए कार्य शीघ्र प्रारंभ करना सुनिश्चित करें।

कांग्रेस नेता डॉ. गोविन्द लाल बल्टियाल ने की पत्रकार वार्ता, मिशन 2027 के तहत संगठन विस्तार और भाजपा सरकार की नाकामियों को जन-जन तक पहुंचाने का किया दावा

के.के.पी संवाददाता

अल्मोड़ा। कांग्रेस नेता डॉ. गोविन्द लाल बल्टियाल एडवोकेट ने एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि मिशन 2027 के तहत कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष सोमेश्वर, हवालबाग, ताकुला एवं कण्डारखुवा के चुनावों में संगठन विस्तार में सक्रिय भागीदारी की गई।उन्होंने कहा कि मिशन 2027 के तहत सोमेश्वर विधानसभा के कई गाँवों / बूथों में जाकर चौपाल लगाकर चुनाव 2027 के संबंध में लोगों को जागरूक किया गया तथा भाजपा सरकार की नाकामियों को विचार गोष्ठियों के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाने का कार्य किया गया।अंकित भण्डारी के कातिलों को मौत की सजा दिलवाये जाने तथा वी.आई.पी. का नाम उजागर किये जाने के लिए सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कई स्थानों पर पुतला दहन व रैलियों के माध्यम से सरकार को चेताने की कोशिश की गई।मिशन 2027 के



तहत भाजपा सरकार की डबल इंजन सरकार की नाकामी जैसे- बेरोजगारी, महंगाई, रिकॉर्ड टैक्स, शिक्षा पर भी टैक्स, महिला अत्याचार, पेपरलीक, वोट चोरी आदि विभिन्न विषयों पर भी विचार गोष्ठियों व रैलियों के माध्यम से आम जनता को जागृत करने की कोशिश की गई। साथ ही भाजपा सरकार के केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा संस्थानों के दुरुपयोग, निर्वाचनों के दुरुपयोग आदि के बारे में आमजन को जागरूक करने की कोशिश की गई।गिरधारी लाल साहू की अनर्गल बयानबाजी एवं ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं मंत्री रेखा आर्या के द्वारा पति पर आरोप तथा पति गिरधारी लाल साहू द्वारा मंत्री पर लगाये गये आरोप पर निष्पक्ष जाँच, मुख्य चुनाव आयुक्त को तत्काल विधिवत बर्खास्त किये जाने हेतु अनेक कार्यक्रम सोमेश्वर विधानसभा के विभिन्न स्थानों में रैली / पुतला दहन एवं विचार गोष्ठियों के माध्यम से किया गया।

आईटीआई कांडा में 26 नवंबर को लगेगा प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला, युवाओं को मिलेगा रोजगार का अवसर



के.के.पी संवाददाता

भारत सरकार की नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम (NAPS) के अंतर्गत जनपद बागेश्वर के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), कांडा में 26 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले (PMNAM) का आयोजन किया जाएगा। जिसमें निजी एवं सरकारी क्षेत्र के विभिन्न प्रतिष्ठानों, जिनमें टाटा मोटर्स, एलाइड रिसोर्सेज, ल्यूमिनस, यूपीईसीएल सहित अन्य कंपनियां प्रतिभाग करेंगी। मेले में जनपद के 8वीं, 10वीं, 12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा एवं स्नातक उत्तीर्ण तथा प्रशिक्षणरत अभ्यर्थी प्रतिभाग कर अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। नोडल प्रधानाचार्य आईटीआई कांडा विनोद कुमार ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी 26 नवंबर 2026 को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कांडा में उपस्थित होकर अथवा जारी क्यूआर कोड के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

18 नवम्बर को हर साल नैनीताल का जन्मदिन सर्वधर्म के साथ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है

के.के.पी संवाददाता

नैनीताल। सरोवर नगरी नैनीताल का 185 वां जन्मदिन सर्वधर्म के साथ बड़ी धूमधाम से हर वर्ष 18 नंवबर खेल के मैदान में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।जिसमें तमाम स्कूल के व कई विभागों एवं संगठनों के लोग केक लाते हैं और सबके साथ काटकर खाते हैं व खिलवाते है।

नैनीताल का जन्मदिन ताल चेनल की निदेशक ईशा साह एवं व्यापार मंडल के अध्यक्ष व सामाजिक कार्यकर्ता मारुति नन्दन साह के सहयोग से बनाया जाता है जिसमें विधायक सरिता आर्या समेत स्थानीय लोगों के अलावा पर्यटक भी जमकर हिस्सा लेते हैं।

यहाँ सर्वधर्म द्वारा नैनीताल के जन्मदिन की सभी लोगों को बधाई दी जाती है। जिसमें हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार पूजा अर्चना एवं यज्ञ आदि किया जाता है तो



वही सिक्ख धर्म , मुस्लिम समुदाय द्वारा एवं क्रिश्चियन धर्म द्वारा भी नैनीताल के लिए परमात्मा से प्राथना एवं निवेदन किया जाता है कि नैनीताल को खुशहाल रखना। इस अवसर पर व्यपार मंडल अध्यक्ष मारुति साह ने कहा यह वह क्षण है 18 नवम्बर जब सारे समुदाय के लोग अपने अपने परमात्मा से विनती करते हैं कि नैनीताल खुशहाल रहे यहाँ के लोग आपसी तालमेल के साथ रहे भाईचारा बने रहे और हर वर्ष 18 नंवबर को नैनीताल का जन्मदिन मनाते रहे। यहाँ नैनीताल की यह विशेषता है कि माँ नैना देवी मंदिर से सटा हुआ गुरुद्वारा है तो सामने मस्जिद और ठीक पीछे चर्च ऐसा कोई शहर हिंदुस्तान में नही होगा जहां से चारों धर्म के नजारे एक साथ देखने को मिल जाये। यहाँ बता दें नैनीताल देश ही नही दुनिया भर में सैर सपाटे के लिये जाना जाता है. इसके बारे में कुछ भी कहना मानो सूरज को रोशनी दिखाना है. 18 नवंबर को सरोवर नगरी नैनीताल का जन्मदिन है. नैनीताल 185 साल का हो चुका है. इन 185 सालों में सरोवर नगरी ने तमाम पड़ाव पार किये. नैनीताल के जन्मदिन के मौके पर नैनीताल खेल मैदान में स्थानीय लोगों के साथ-साथ तमाम संगठनों ने केक काटा. बता दें 1841 में अंग्रेज व्यपारी पीटर बैरन ने नैनीताल की खोज की थी. 1841 में नैनीताल खोज के बाद पीटर बैरन ने यहां वसावट शुरू की. समुद्ध तल से 1938 मीटर ऊंचाई पर स्थित नैनीझील इस शहर का प्रमुख आर्कषण है. जहां देश ही नहीं बल्कि विदेशों एवं दुनियाभर के सैलानी पहुंचते हैं. नैनी झील में नोकाविहार का लुफ्त उठाने के लिए।

भीमताल में कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक, बूथ स्तर पर 10-10 कार्यकर्ताओं की टीम बनाने के निर्देश

के.के.पी संवाददाता

भीमताल। विधानसभा भीमताल के ब्लाक मुख्यालय धारी में अध्यक्ष सतीश चंद्र आर्य की अध्यक्षता में संपन्न हुई विधानसभा की शंकर आत्मक संगनात्मक बैठक में जिला प्रभारी एवं प्रदेश महामंत्री डॉ गणेश उपाध्याय ने सभी कांग्रेस जनों को एक जुड़ता का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि भीमताल की जनता बदलाव के लिए तैयार है ।इस स्थिति में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घर-घर भाजपा सरकार की जन्म विरोधी नीतियों से अवगत कराना होगा। सभी ब्लॉक अध्यक्षों को प्रत्येक बूथ पर 10 -10 कार्यकर्ताओं की टीम बनाकर शीघ्र ही बूथ सम्मेलन आयोजित करने के निर्देश दिए। प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश नैनवाल ने संगठन ने बैठक में संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा



सरकार में भ्रष्टाचार व व्यभिचार शिष्टाचार हो चुका है । प्रत्येक विधानसभा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जनता भाजपा को सत्ता से बेदखल करने को तैयार है ।जिला अध्यक्ष राहुल छिमवाल ने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव में पार्टी से घोषित होने वाले प्रत्याशी एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प ले । विधानसभा प्रभारी श्री विपिन खोलिया ने कहा कि शीघ्र ही प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे । सभी कांग्रेसजनो की सामूहिक भागीदारी से विधानसभा जीत दर्ज करेगी। बैठक में गोपाल बिष्ट, डॉक्टर केदार पलाडिया, हरीश पनेरु, राकेश बृजवासी, लाखन नेगी, ब्लॉक अध्यक्ष हरीश बोरा, महिला अध्यक्ष खष्टी बिष्ट, सतीश टम्टा ,इंटक नेता विपिन चंद्रा, प्रेम मेहरा आदि सैकड़ो कांग्रेसजन उपस्थित थे।

मंत्री राम सिंह कैड़ा के प्रयासों से ओखलकांडा ब्लॉक के वारी गाँव की सड़क के लिए 84 लाख स्वीकृति

आजादी के बाद वारी गाँव पहुंचेगी सड़क-मंत्री राम सिंह कैड़ा

ग्रामीणों वर्षो से कर रहे थे मोटर मार्ग निर्माण की मांग

मंत्री राम सिंह कैड़ा ने किया ग्रामीणों का सपना साकार

के.के.पी संवाददाता

भीमताल। ओखलकांडा ब्लॉक के ग्राम सभा कटना से वारी के ग्रामीणों आजादी से आज तक मोटर मार्ग निर्माण करने की मांग कर रहे थे मोटर मार्ग नहीं होने से ग्रामीणों को मुख्य मार्ग तक अपना सामान लाने, मरीजो को घोडो या कंधे में लाना पड़ता था! किसानों को अपनी उपज को मंडी पहुंचने तक सारा पैसा किराये भाड़े मै लग जाता था !यहा के लोगो को काफी परेशानियों का समाना करने पड़ता था! ग्रामीणों ने कहा यहां के



ग्रामीणों ने पूर्व मै कई जनप्रतिनिधियों से भी मोटर मार्ग बनाने की मांग की लेकिन किसी ने ग्रामीणों की नहीं सुनी!

ग्रामीणों ने मंत्री राम सिंह कैड़ा से मोटर मार्ग के निर्माण करने की मांग की! मंत्री कैड़ा ने जनता की समस्याओं को देखते हुऐ पहले मोटर मार्ग बनाने हेतु वन व पर्यावरण विभाग से स्वीकृति कराई जिसके राज्य योजना के तहत विभाग के अधिकारियो से डीपीआर तैयार कर शासन को भेजनें को कहा था, मंत्री कैड़ा ने मुख्यमंत्री से मोटर मार्ग निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत करने की मांग की! मंत्री कैड़ा ने कटना से वारी मोटर मार्ग निर्माण के लिए शाशन से लगभग 84लाख धनराशि स्वीकृति कराकर जिसका शासनादेश जारी हो गया हैं मंत्री कैड़ा ने विभाग के अधिकारियो शीघ्र टैण्डर प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं मंत्री कैड़ा ने कहा जल्दी ही मोटर मार्ग का निर्माण कार्य शुरू किया जायेगा! कार्य पूर्ण होने के बाद ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान हो जायेगा! क्षेत्र के लोगो ने मंत्री कैड़ा का धन्यवाद दिया! मंत्री कैड़ा ने कहा मेरा प्रयास है हर गाँव को सड़क से जोड़ सकू जिस दिशा मै कार्य किया जा रहा है!

कालाढुंगी: कोटाबाग में वृहद ऋण वितरण मेला आयोजित, किसानों और महिला समूहों को मिला 0% ब्याज पर ऋण

के.के.पी संवाददाता

कालाढुंगी। सहकारिता विभाग, जनपद नैनीताल के तत्वावधान में कोटाबाग ब्लॉक सभागार में किसानों और महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक 'वृहद् ऋण वितरण मेले' का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के जिला अध्यक्ष रविन्द्र सिंह रेकुनी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना करना और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है।जिसमें ?दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को पशुपालन, कुक्कुट पालन (पोल्ट्री), मशरूम उत्पादन और बागवानी के लिए 3 लाख रुपये तक तथा फसलों की बुआई के लिए 1 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त (0% ब्याज) ऋण वितरित किया गया। महिला स्वयं सहायता समूहः महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए 5 लाख रुपये



तक का ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया।

कुक्कुट वैली योजनाः कोटाबाग ब्लॉक में इस योजना के अंतर्गत अब तक 266 कृषकों को 257.60 लाख रुपये का ऋण और 28,100 चूजे प्रदान किए जा चुके हैं। रीप परियोजनाः इस परियोजना के तहत महिलाओं को 30, हजार रुपये के अनुदान के साथ ऋण सहायता दी जा रही है।? इस दौरान मुख्य अतिथि दर्जा राज्य मंत्री सुरेश भट्ट व दर्जा राज्य मंत्री शांति मेहरा ने सयुक्त रूप से कहा? केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो योजना है–उन योजनाओं का लाभ उठाकर किसान हमारा समृद्धिशाली हो, किसान की आय दुगनी की जाए–उसके तहत हर किसान को 0% ब्याज पर सहकारिता विभाग की ओर से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। किसान के साथ-साथ जो हमारे स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, उनको भी 0% ब्याज पर ऋण दिया जा रहा है। (जैसे किसान सम्मान निधि, सॉइल हेल्थ कार्ड, फसल बीमा योजना, नीम कोटेड यूरिया और सिंचाई योजनाएं) का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देश और प्रदेश के किसान आगे बढ़ रहे हैं और खुशहाल हो रहे हैं। वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के संकल्प को पूरा करने के लिए 'विकसित उत्तराखंड' और उसके लिए 'विकसित किसान' की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं।इस दौरान महाप्रबंधक दिगम्बर सिंह, खंड विकास अधिकारी श्वेता सिंह, सहकारिता अधिकारी प्रेम प्रकाश, कोटाबाग ब्लॉक की डायरेक्टर विमला अटवाल, सैलपसाव समिति के चंदन पांडे, सहकारिता समिति के उपाध्यक्ष हरीश अटवाल, सहकारिता समिति की अध्यक्ष पुष्पा खोलिया, सहित कुंदन जंतवाल, मीनाक्षी जंतवाल, सौण प्रधान समिति से खीम सिंह बिष्ट, दुरेश देवपा, सुच्चा सिंह, किरन कुँवर, ध्यानलल्म खड़ायत, भगवान कुमटिया, निर्मल अग्रवाल, प्रधान चंद्रप्रकाश सनवाल उपस्थित रहे।

कुमाऊँ कमिश्नर दीपक रावत ने भरा स्व-गणना फार्म

कुमाऊँ कमिश्नर दीपक रावत ने कैम्प कार्यालय से स्व- गणना का ऑनलाइन फॉर्म भरा।

के.के.पी संवाददाता

हल्द्वानी। आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि 16 नवम्बर से 30 नवम्बर 2026 तक भारत सरकार द्वारा स्वगणना का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनगणना केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह हमारे देश के भविष्य और विकास की आधारशिला है। आपकी सही जानकारी से ही सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी बेहतर योजनाएं बनाने में मदद मिलती है। आयुक्त ने कहा कि जनगणना में अपनी जानकारी दर्ज कराने के लिए प्रगणक (Enumerator) के घर आने का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई (Self&Enumeration) सुविधा के माध्यम से आप घर बैठे, अपनी सुविधानुसार ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए अपने और अपने



परिवार का विवरण स्वयं भर सकते हैं। आयुक्त ने कहा कि इससे समय की बचत आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय फॉर्म भर सकते हैं साथ ही स्वयं जानकारी ऐप में भरने से त्रुटि की सम्भावना नही रहती तथा सभी जानकारियां गोपनीय रहती हैं।

उन्होने कहा जनगणना पोर्टल (se.census.gov.in) पर जायें अपने परिवार के सभी सदस्यों का विवरण भरे तथा पोर्टल में दिये गये सभी 40 प्रश्नों का विवरण सबमिट करने के पश्चात स्वगणना आईडी को सुरक्षित रखें जब प्रगणक आपके घर आये तो उन्हें केवल आईडी दिखाए। आयुक्त दीपक रावत ने लोगों से अपील की है कि एक जागरूक नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं। आज ही स्वगणना करें और राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।

अति आवश्यक सूचना

गुमशुदा की तलाश करने में सहयोग करें।



ग्रुप में जुड़े सभी भाई बंधुओं को सूचित किया जाता है कि मोहन चंद्र उपाध्याय (उर्फ मनोज), पुत्र श्री माधवानंद उपाध्याय, निवासी ग्राम पिपना, उम्र लगभग 23 वर्ष, कल दिनांक 16 नवम्बर 2026 को प्रातः लगभग 9:45 बजे अपने निवास स्थान नाथूपुरा, बुराड़ी (दिल्ली) से कोचिंग सेंटर तलाश करने के बहाने घर से निकला था। घर के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज में उसे लगभग 9:53 बजे घर से जाते हुए देखा गया है। उसके बाद से वह घर वापस नहीं लौटा है। वह अपने साथ मोबाइल फोन भी नहीं ले गया है, जिस कारण उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है।

मनोज का पिछले कुछ वर्षों से अध्यात्म की ओर विशेष झुकाव रहा है।

अतः आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि यदि किसी भी व्यक्ति को मोहन चंद्र उपाध्याय (मनोज) के संबंध में कोई जानकारी मिले अथवा वे कहीं दिखाई दें, तो कृपया तत्काल नीचे दिए गए मोबाइल नंबरों पर परिवार को सूचित करने का कष्ट करें।

आपकी छोटी-सी सूचना भी परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है। कृपया इस सूचना को अधिक से अधिक लोगों एवं व्हाट्सऐप समूहों में साझा करें, ताकि मनोज को शीघ्र खोजने में सहायता मिल सके।

संपर्क सूत्रः

श्री माधवानंद उपाध्याय (पिता) - 9627586426

योगेश उपाध्याय - 8979907940

परिवार आप सभी के सहयोग एवं सहायता का आकांक्षी है।

कृपया इस सूचना को अधिक से अधिक प्रसारित करें।

त्योहारों की खुशियों के साथ आत्मनिर्भरता की नई मिठास घोल रहीं गौलापार की महिलाएं, 50 हजार के निवेश से कमाया 90 हजार का मुनाफा

के.के.पी संवाददाता

हल्द्वानी/नैनीताल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आत्मनिर्भर उत्तराखंड के संकल्प को धरातल पर साकार करने में प्रदेश की महिलाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं स्थानीय संसाधनों और अपने हुनर को स्वरोजगार से जोड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। इसी की एक प्रेरक मिसाल हल्द्वानी के गौलापार स्थित मंगलम ग्राम संगठन की महिलाओं ने पेश की है। ग्राम संगठन से जुड़ी छह महिलाओं ने नवरात्रि और दीपावली के त्योहारों को स्वरोजगार के अवसर में बदलते हुए अपने हाथों से शुद्ध एवं बिना मिलावट के गट्टे, बतासे और खिलौने तैयार किए। महिलाओं ने इन उत्पादों की बिक्री



स्थानीय बाजारों और हल्द्वानी में की। उनके उत्पादों को ग्राहकों का अच्छा प्रतिसाद मिला और इस छोटी-सी पहल ने उन्हें उल्लेखनीय आर्थिक लाभ दिलाया।

50 हजार के निवेश से 1.40 लाख की बिक्री

मंगलम ग्राम संगठन की महिलाओं ने इस कार्य की शुरुआत कुल 50 हजार रुपये की लागत से की। त्योहारों के दौरान मांग को देखते हुए उन्होंने पारंपरिक गट्टे, बतासे और खिलौने तैयार कर बाजार में बिक्री की। मेहनत, गुणवत्ता और शुद्धता के प्रति विश्वास का परिणाम रहा कि मात्र नवरात्रि और दीपावली के दौरान समूह ने कुल 1 लाख 40 हजार रुपये की बिक्री की।

इसमें से सभी खर्चों के बाद समूह को लगभग 90 हजार रुपये का शुद्ध मुनाफा प्राप्त हुआ। इस प्रकार संगठन की प्रत्येक महिला के हिस्से में 15 हजार रुपये का लाभ आया। यह उपलब्धि दर्शाती है कि सामूहिक प्रयास, स्थानीय उत्पादों और स्वरोजगार के माध्यम से महिलाएं कम निवेश में भी अपनी आमदनी बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ सकती हैं।

शुद्धता और पारंपरिक उत्पाद बने सफलता का आधार

समूह की महिलाओं ने अपने उत्पादों को स्वयं तैयार किया और उनकी शुद्धता एवं गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया। त्योहारों पर पारंपरिक उत्पादों की मांग को देखते हुए उन्होंने स्थानीय बाजार में अपनी अलग पहचान बनाई। इस पहल से एक ओर लोगों को घर पर तैयार शुद्ध सामग्री उपलब्ध हुई, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को अपनी मेहनत का आर्थिक लाभ भी मिला।

राज्य सरकार एवं NRLM के प्रति जताया आभार

मंगलम ग्राम संगठन की महिलाओं ने अपनी इस उपलब्धि पर राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) का हृदय से आभार व्यक्त किया है। महिलाओं ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को संगठित होकर कार्य करने, स्वरोजगार अपनाने और आर्थिक रूप से सशक्त बनने की दिशा में प्रोत्साहन मिल रहा है। उन्होंने राज्य सरकार एवं NRLM के प्रयासों और सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन मिलने की अपेक्षा जताई।

महिला आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरक पहल

यह सफलता केवल 90 हजार रुपये के मुनाफे तक सीमित नहीं है, बल्कि महिला सशक्तीकरण, सामूहिक उद्यमिता और स्थानीय उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने की क्षमता का भी उदाहरण है। मंगलम ग्राम संगठन की ये महिलाएं साबित कर रही हैं कि यदि महिलाओं को अवसर, उचित मार्गदर्शन और सामूहिक प्रयास का मंच मिले, तो वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ ही आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं।

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय का 11वाँ दीक्षांत समारोह गरिमामय वातावरण में संपन्न, 14,857 शिक्षार्थियों को डिजिलॉकर के माध्यम से उपाधियाँ प्रदान की गयी

राज्यपाल एवं कुलाधिपति डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने आठ शोधार्थियों को पीएच.डी. उपाधि तथा 36 मेधावी शिक्षार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए; प्रख्यात प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय विशेषज्ञ अश्वनी लोहनी को मानद उपाधि से किया गया सम्मानित

के.के.पी संवाददाता

हल्द्वानी। उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी का 11वाँ दीक्षांत समारोह गरिमामय एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। समारोह में उत्तराखण्ड के माननीय राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉ. ढाल सिंह बिसेन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्रदेश के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत विशिष्ट अतिथि तथा राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष एवं उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय



के पूर्व कुलपति प्रो. नागेश्वर राव विशेष अतिथि के रूप में समारोह में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर प्रख्यात प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय विशेषज्ञ तथा भारतीय रेल सेवा के 1980 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री अश्वनी लोहनी को मानद उपाधि प्रदान की गई।

समारोह का शुभारंभ विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के अनावरण के साथ हुआ। माननीय राज्यपाल एवं अन्य अतिथियों ने प्रतिमा का अनावरण किया। इसके पश्चात विश्वविद्यालय की शौर्य दीवार पर पुष्प अर्पित कर देश के वीर सपूतों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान व्यक्त किया गया।

मुख्य दीक्षांत समारोह का संचालन विश्वविद्यालय के कुलसचिव श्री खेमराज भट्ट ने किया। प्रारंभ में विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रो. नवीन चन्द्र लोहनी ने माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति डॉ. ढाल सिंह बिसेन, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, विशिष्ट अतिथि प्रो. नागेश्वर राव तथा मानद उपाधि प्राप्तकर्ता श्री अश्वनी लोहनी का स्वागत किया। इसके उपरांत उन्होंने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक एवं वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कुलपति प्रो. नवीन चन्द्र लोहनी ने बताया कि विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के 21 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और वर्ष 2026 में उत्तराखण्ड देश का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बना है। उन्होंने जानकारी दी कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के अंतर्गत विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों में अध्ययन पूर्ण करने वाले 14,857 शिक्षार्थियों को उपाधियाँ डिजिलॉकर के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त आठ शोधार्थियों को पीएच.डी. उपाधि तथा 36 मेधावी शिक्षार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए जा रहे हैं। इन 36 स्वर्ण पदकों में 30 विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, दो कुलाधिपति स्वर्ण पदक तथा चार प्रायोजित स्वर्ण पदक शामिल हैं।

अपनी प्रगति रिपोर्ट में कुलपति ने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक, शोध एवं सामुदायिक पहलों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय वर्तमान में 8 क्षेत्रीय केंद्रों एवं 144 अध्ययन केंद्रों के माध्यम से संचालित हो रहा है तथा इस वर्ष हरिद्वार में नया क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा 94 शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इनमें डिप्लोमा इन भगवद्गीता स्टडीज, मानवाधिकार प्रमाण-पत्र तथा कुमाऊँनी, गढ़वाली, नेपाली एवं जापानी भाषा के पाठ्यक्रम शामिल हैं।

नशे में धुत कार चालक ने स्कूटी में मारी जोरदार टक्कर, तीन स्कूली बच्चों समेत चार घायल

के.के.पी संवाददाता

कालाढूंगी। कालाढूंगी हल्द्वानी मुख्य मार्ग पर एचडीएफसी बैंक के समीप एक तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने आगे चल रही स्कूटी को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण सड़क हादसे में स्कूटी चालक और उस पर सवार दो स्कूली बच्चों सहित सड़क किनारे पैदल जा रहा एक चार वर्षीय मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया।?प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी सवार छिटक कर दूर जा गिरे। इस दुर्घटना में स्कूटी चालक की एक टांग बुरी तरह फ्रैक्चर हो गई है, जबकि स्कूटी पर बैठे दोनों स्कूली बच्चों को भी गंभीर चोटें आई हैं। इसी दौरान वहां से पैदल गुजर रहा एक चार साल का मासूम भी अनियंत्रित कार की चपेट में आकर बुरी तरह जख्मी हो गया।

?हादसे के तुरंत बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और भारी



भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों और 108 एंबुलेंस सेवा की मदद से सभी घायलों को तत्काल नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें हल्द्वानी स्थित डॉ. सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय (स्ञ॥) के लिए रेफर कर दिया है।

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि आरोपी कार चालक शराब के नशे में पूरी तरह धुत था। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए चालक को मौके पर ही दबोच लिया और सूचना देकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को अपने कब्जे में ले लिया है और आरोपी चालक के खिलाफ अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

राष्ट्रीय स्तरीय सरस मेले में व्यावसायिक स्टॉल आवंटन हेतु 20 नवम्बर तक करा सकते हैं पंजीकरण

के.के.पी संवाददाता

हल्द्वानी। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जनपद नैनीताल में राष्ट्रीय स्तरीय सरस मेला 2026-27 का आयोजन 24 नवम्बर से 03 दिसम्बर 2026 तक एमबी इंटर कॉलेज मैदान, हल्द्वानी में किया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया कि मेले के सफल आयोजन के लिए मेला पंजीकरण एवं आवंटन समिति द्वारा स्टॉल आवंटन की प्रक्रिया संचालित की जा रही है। मेले में व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अभी 10 कमर्शियल स्टॉल शेष हैं। उन्होंने बताया कि इच्छुक उद्यमियों एवं व्यवसायियों से अपील की है कि वे सरस मेले में अपने उत्पादों एवं व्यावसायिक गतिविधियों के प्रदर्शन हेतु स्टॉल आवंटन के लिए 20 नवम्बर 2026 तक अपना पंजीकरण करा सकते हैं। स्टॉल आवंटन एवं पंजीकरण से संबंधित अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 8755052509 पर संपर्क किया जा सकता है।

शक्तिफार्म सुखी नदी में बेखौफ जारी अवैध मिट्टी खनन का कारोबार

प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर मिट्टी माफिया कर रहे खेल,

जिम्मेदार बेखबर

सरकारी कार्यालयों के आसपास मुखबिरों का जाल

प्रशासन की कार्रवाई से पहले ही मिल जाती है सूचना

के.के.पी संवाददाता

दीपक भारद्वाज/शक्तिफार्म। क्षेत्र की सुखी नदी में अवैध मिट्टी खनन का कारोबार बड़े पैमाने पर जारी है। मिट्टी खनन माफिया प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर दिन-रात इस अवैध कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। आरोप है कि खनन माफियाओं ने प्रशासनिक कार्रवाई से बचने के लिए सरकारी कार्यालयों और जिम्मेदार अधिकारियों के आसपास मुखबिरों का जाल फैला रखा है। ये मुखबिर प्रशासन की गतिविधियों पर नजर रखते हैं और



कार्रवाई की भनक लगते ही खनन कारोबारियों को सूचना दे देते हैं। यही वजह है कि प्रशासन की ओर से कार्रवाई की तैयारी के बावजूद अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश नहीं लग पा रहा है। शक्तिफार्म की सुखी नदी में बड़े पैमाने पर मिट्टी की खुदाई की जा रही है। इसके अलावा क्षेत्र के उपजाऊ खेतों को भी निशाना बनाया जा रहा है। मिट्टी खनन माफिया नदी और खेतों से मिट्टी निकालकर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और डंपर के माध्यम से मुख्य सड़कों से होते हुए मांग वाले क्षेत्रों तक पहुंचा रहे हैं। आरोप है कि प्रतिबंध के बावजूद मिट्टी से भरे भारी वाहन बेखौफ सड़कों पर दौड़ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग इन पर प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार, अवैध खनन में शामिल लोगों ने सरकारी कार्यालयों के आसपास अपने मुखबिर सक्रिय कर रखे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की गतिविधियों और छापेमारी की तैयारियों पर लगातार नजर रखी जाती है। जैसे ही किसी कार्रवाई की भनक लगती है, इसकी सूचना खनन कारोबारियों तक पहुंचा दी जाती है। इससे प्रशासनिक कार्रवाई से पहले ही खनन स्थल खाली कर दिए जाते हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र जांच होना भी जरूरी है।

जिलाधिकारी की ओर से अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं, इसके बावजूद सुखी नदी में खनन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में गठित टीमों की निगरानी और कार्रवाई की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठने लगे हैं।

पर्यावरण और ग्रामीण जीवन पर पड़ रहा गंभीर असर

लगातार हो रही खुदाई से खेतों और नदी का प्राकृतिक स्वरूप बिगड़ रहा है। कई स्थानों पर बड़े-बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जो बरसात के दौरान हादसों का कारण बन सकते हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि मिट्टी से भरे भारी वाहनों की लगातार आवाजाही से गांवों की सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। वहीं, उड़ती धूल के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि यदि समय रहते अवैध खनन पर रोक नहीं लगाई गई तो क्षेत्र का भूजल स्तर प्रभावित होने के साथ पर्यावरण संतुलन भी बिगड़ सकता है। ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर अवैध खनन में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।

प्रशासन की चुप्पी पर उठ रहे सवाल

क्षेत्र में लगातार अवैध मिट्टी खनन होने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ रही है। लोगों का सवाल है कि जब दिन-रात मिट्टी से भरे वाहन मुख्य सड़कों से गुजर रहे हैं तो जिम्मेदार विभागों को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिल रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही अवैध खनन पर प्रभावी रोक नहीं लगाई गई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

संपादकीय

आर्थिक तबाही के कगार पर खड़ा भारतः राहुल गांधी

बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाहिर की चिंता

कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का दो दिवसीय अमेरिका दौरा भारतीय राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण बन गया है। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों और शिक्षाविदों के बीच संवाद करते हुए राहुल गांधी ने भारतीय अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, भारत आर्थिक तबाही के कगार पर खड़ा है। देश में बेरोजगारी की बड़ी समस्या है। शिक्षा व्यवस्था भी गंभीर चुनौतियों से गुजर रही है। उनका कहना था, इन समस्याओं को नजरअंदाज करने से उनका समाधान नहीं होगा। राहुल गांधी के इस बयान को केवल राजनीतिक आरोप मानकर खारिज करना उचित नहीं होगा। यह जरूर है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था को तबाही के कगार पर बताना एक बड़ा राजनीतिक दावा है, इसके पीछे उठाए गए बेरोजगारी, रोजगार सृजन और शिक्षा की गुणवत्ता जैसे सवालों पर गंभीर चर्चा भारत में जरूरी है। सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप अपनी जगह हैं। देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य किसी भी राजनीतिक दल के लिए बड़ा विषय है। भारत में आज उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं की संख्या करोड़ों में है। इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्रियां लेकर निकलने वाले युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार की है। शिक्षा पूरी करने के बाद भी यदि उन्हें अपनी योग्यता के अनुरूप नौकरी नहीं मिलती, ऐसी स्थिति में उनके भीतर निराशा पैदा होना स्वाभाविक है। राहुल गांधी ने इसी वर्ग का उल्लेख करते हुए कहा, मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के अनेक युवा औपचारिक शिक्षा पूरी करने के बावजूद अपना भविष्य सुरक्षित नहीं देख पा रहे हैं। भारत में जिस तरह के समाचार मिल रहे हैं उसमें पढ़े-लिखे डिग्री धारी युवा अब अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने लगे हैं। यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है। उनके अनुसार, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच वैचारिक दूरी भी बढ़ रही है। माता-पिता जिस शिक्षा और करियर के रास्ते को सफलता का माध्यम मानते रहे हैं। आज की पीढ़ी को उसमें पहले जैसी संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही हैं। युवा अपने सपनों के अनुरूप सफलता चाहते हैं। अवसरों की कमी उनके भीतर असंतोष पैदा कर रही है। वैचारिक मतभेद में अर्थ-व्यवस्था का आधार मजबूत करना जरूरी हो गया है।

राहुल गांधी ने अपने संबोधन में छोटे और मध्यम उद्योगों तथा कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया। उनका तर्क है, केवल सेवा क्षेत्र के सहारे देश की विशाल युवा आबादी को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। इसके लिए विनिर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना होगा। उन्होंने मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं की सफलता पर भी सवाल उठाए। उनके मुताबिक छोटे उद्योगों में रोजगार पैदा करने की क्षमता है, उन्हें पर्याप्त अवसर और निवेश नहीं मिल रहे हैं। भारत के सामने वास्तविक चुनौती यह है, आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। बड़े उद्योगों और कंपनियों का विस्तार अपनी जगह महत्वपूर्ण है। भारत में कुछ लोग अमीर हो रहे हैं, मध्य और निम्न वर्ग आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। जब तक छोटे कारोबार, कृषि, लघु-उद्योग और स्थानीय उत्पादन को मजबूती नहीं मिलेगी, तब तक व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना तथा आर्थिक संतुलन बनाना कठिन होगा।

धर्मनिष्ठ सत्ता और ज़हरीले पानी में धर्मावलम्बी?

निर्मल रानी

स्विट्ज़रलैंड की वायु गुणवत्ता निगरानी संस्था एयर आईक्यू की 2026 में जारी हुई वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली दुनिया का चौथा सबसे प्रदूषित शहर और लगातार आठवें वर्ष विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी रही। नवंबर 2026 के दूसरे सप्ताह विशेषकर 7 नवंबर और 13-16 नवंबर के दौरान एयर आईक्यू की लाइव रैंकिंग में दिल्ली कई बार लाहौर, कोलकाता और ढाका को पीछे छोड़कर दुनिया का प्रथम सबसे प्रदूषित प्रमुख शहर बन गया। इस दौरान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों में दिल्ली का औसत, तक़रीबन 400 के पार अर्थात गंभीर श्रेणी तक पहुंच गया, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी और आईटीओ जैसे कुछ इलाक़ों में यह 450 से ऊपर दर्ज किया गया।और इसी घोर प्रदूषित राजधानी में गत दिनों उत्तर भारत विशेषकर बिहार का सर्वाधिक लोकप्रिय धार्मिक व सामाजिक त्यौहार छठ मनाया गया। वर्तमान में केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम तीनों ही स्तरों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गोया दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। नवंबर 2026 में छठ महापर्व के आयोजन को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों ख़ासकर छठ पूजा हेतु श्रद्धालुओं को साफ़ यमुना जल उपलब्ध कराने, दिल्ली के 1,400 से अधिक घाटों के निर्माण और अभूतपूर्व नागरिक सुविधाओं के बड़े दावे किए थे। सरकार का मुख्य ज़ोर इस बात पर था कि इस वर्ष श्रद्धालुओं को बिना किसी गंदिगी या ज़हरीले झाग के, भव्य रूप से पूजा करने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने छठ पूजा से ठीक पहले यह भी दावा किया था कि बीजेपी सरकार की तैयारियों के तहत यमुना का पानी साफ़ है और इसमें कोई गंदगी या झाग नहीं है। उन्होंने कहा था कि इस बार व्रती महिलाएं स्वच्छ यमुना जल में ही सूर्य देव को अर्घ्य देंगी। दिल्ली सरकार ने यह भी दावा किया था कि यमुना नदी के पानी को पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल (इको-फ्रेंडली) उपचारित किया जा रहा है, जिससे पानी या जलीय जीवों पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। सरकार ने राजधानी भर में लगभग 1,482 छठ घाट तैयार करने का दावा किया था जो पिछले वर्ष के 1,326 घाटों की तुलना में अधिक थे। सभी बुनियादी तैयारियां 6 नवंबर 2026 तक पूरी करने के निर्देश दिए गए थे। उत्तरी दिल्ली में आउटर रिंग रोड से इंद्रलोक तक मुनक नहर के दोनों किनारों पर लगभग 15 करोड़ रुपये की लागत से 11 किलोमीटर लंबा भव्य छठ घाट बनाने और उसमें साफ़ पानी छोड़ने का दावा किया गया था। सरकार ने सभी घाटों पर स्वच्छता, निर्बाध बिजली, रोशनी, पीने के पानी, मोबाइल शौचालय, चेंजिंग रूम और चिकित्सा सुविधाओं के पुख्ता प्रबंध किये जाने का दावा भी किया था।

परन्तु नए कृत्रिम या नहर घाटों के निर्माण के मोर्चे पर तो सरकार अपने कई दावों को पूरा करने में कुछ हद तक सफल ज़रूर रही परन्तु यमुना नदी को पूरी तरह साफ़ और झाग-मुक्त बनाने का उसका सबसे प्रमुख दावा ज़मीनी स्तर पर पूरा नहीं हो सका। ग़ौरतलब है कि सरकार ने दावा किया था कि छठ पूजा के दौरान इस बार यमुना नदी में ज़हरीला सफ़ेद झाग नहीं दिखेगा। 15 और 16 नवंबर 2026 को छठ पूजा के संध्या और उषा अर्घ्य के दौरान कालिंदी कुंज सहित यमुना के कई हिस्सों में श्रद्धालु कमर तक गहरे पानी और सफ़ेद झाग की मोटी परतों के बीच पूजा करते नजर आए। दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने स्वयं स्वीकार किया कि कालिंदी कुंज के बड़े हिस्सों में झाग तैरता हुआ दिखाई दिया। नदी में बिना उपचारित सीवर के पानी, औद्योगिक कचरे और डिटर्जेंट के मिलने से पानी की सतह पर इसतरह का ज़हरीला सफ़ेद झाग बनता है।

देवभूमि में देर से मनाई जाती है बूढ़ी दीपावली !

डॉ श्रीगोपाल नारसन

देवभूमि उत्तराखंड व हिमाचल के पर्वतीय इलाकों को छोड़कर शायद ही किसी ने इगास के बारे में सुना होगा। आजकल के पर्वतीय मूल के बच्चों को भी इगास का पता नहीं है कि इगास नाम का कोई त्यौहार भी होता है,।

पर्वतीय मूल के लोगो की असली दीपावली इगास ही है, जो दीपोत्सव के ठीक ग्यारह दिन बाद ओर कही कही एक माह बाद मनाई जाती है।दीपोत्सव को इतनी देर से मनाने के दो कारण हैं पहला कारण भगवान श्रीराम के अयोध्या वापस आने की खबर सूदूर पहाडी निवासीयों को ग्यारह दिन बाद ?र कही कही एक माह बाद मिली, और उन्होंने उस दिन को ही दीपोत्सव के रूप में हर्षोल्लास से मनाने का निश्चय किया, बाद में पहाड़ में भी छोटी दीपावली से लेकर गोवर्धन पूजा व भैयादूज तक सब पर्वों को मनाया जाने लगा, लेकिन अपनी परंपरा के मुताबिक ग्यारह दिन या फिर एक माह बाद की उस दीवाली को पहाड़ के लोगो ने मनाना नहीं छोडा, ।

पहाडों में दीपावली को लोग दीये जलाते हैं, गौ पूजन करते हैं, अपने ईष्ट कुलदेवी कुलदेवता की पूजा करते हैं। नयी उडद की दाल के पकौड़े बनाते हैं और गहत की दाल के स्वांले (दाल से भरी पुड़ी) बूढ़ी दीपावली का खास व्यंजन है। दीपावली और इगास की शाम को सूर्यास्त होते ही औजी हर घर के द्वार पर ढोल दमाऊ के साथ बडई (एक तरह की ढोल विधा) बजाते हैं, फिर लोग पूजा शुरू करते हैं, पूजा समाप्ति के बाद सब लोग ढोल दमाऊ के साथ कुलदेवी या देवता के मंदिर जाते हैं वहां पर मंडाण (पहाडी नृत्य) नाचते हैं, चीड़ की राल और बेल से बने भैला (एक तरह की मशाल) खेलते हैं, रात के बारह बजते ही सब घरों से इकट्ठा किया गया सतनाजा (सात प्रकार का अनाज)जिसे गांव की चारो दिशा की सीमाओं पर रखते हैं, इस सीमा को दिशाबंधनी कहा जाता है। ये सतनाजा मां काली को भेंट होता है। इगास मनाने का दूसरा कारण है गढवाल नरेश महिपति शाह के सेनापति वीर माधोसिंह गढवाल तिब्बत युद्ध में गढवाल की सेना का नेतृत्व कर रहे थे, गढवाल सेना युद्ध जीत चुकी थी लेकिन माधोसिंह सेना की एक छोटी टुकडी के साथ मुख्य सेना से अलग होकर भटक गये, सबने उन्हें वीरगति को प्राप्त मान लिया लेकिन वो जब वापस आये तो सबने उनका स्वागत बडे जोरशोर से किया ,ये दिन दीपोत्सव के ग्यारह दिन बाद का दिन था,इसलिए इस दिन को भी दीपोत्सव जैसा मनाया गया। उस युद्ध में माधोसिंह गढवाल - तिब्बत की सीमा तय कर चुके थे जो वर्तमान में भारत- तिब्बत सीमा है ।

पहाडी इगास लुप्त होने वाले त्यौहारों की श्रेणी में है, इसका मुख्य कारण बढता बाजारवाद, क्षेत्रिय लोगों की उदासीनता और पलायन है, ।

इस त्यौहार को बूढ़ दवैली, बूढ़ी दिआऊड़ी, दयाउली भी कहा जाता है। इस पारम्परिक आयोजन से जुड़ी किवदंतियां महाभारत व रामायण युग से सम्बन्धित हैं। पहाड़ी इलाकों में श्रीराम के अयोध्या लौटने की खबर देर से पहुंची और तब तक पूरा देश दीवाली मना चुका था फिर भी पहाड़ी निवासियों ने दीपोत्सव मनाया जिसका नाम पड़ गया बूढ़ी दीवाली पड़ गया।

बूढ़ी दिवाली आयोजनों में अभिमन्यु के चक्रव्यूह भेदने के दृश्य को खास अंदाज में मंचित किया जाता है। अखाड़े में लोग रस्सियों का एक घेरा बना उसे थामे रहते हैं। बीच में एक व्यक्ति हाथ में लाठी थामे रहता है। निश्चित समय पर संकेत से रस्सी का घेरा तंग किया जाता है बीच में खड़े अभिमन्यु को जकड़ने की कोशिश की जाती है वह घेरा तोड़ने का प्रयास करता है और सफल होकर दिखाता है। यह क्रिया कई बार दोहराई जाती है। इस चक्रव्यूहिक आयोजन में लोग कई बार जख्मी हो जाते हैं। मगर उल्लास और उमंग के वातावरण में कोई परवाह नहीं करता। इससे पहले अमावस की संध्या को टूटी लकड़ियाँ इक्कठी की जाती हैं व मेला स्थल दशनामी में रात्रि की पूवार्ध में पूजन कर उनमें आग लगा दी जाती है। लोग गाते हुए 'पांडव नृत्य' करते हैं। मध्य रात्रि को पांडव कौरव संघर्ष अभिनीत किया जाता है, कौरव पांडवों पर आक्रमण करते हैं, पांडव डटकर मुकाबला कर जीतते हैं फिर जश्न होता है। पूरी रात विजयोल्लास में परिवर्तित हो जाती हैं।

सिरमौर में मूल दीवाली के दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में काम की अधिकता होती है। यहां इन दिनों घासनियों (घास उगाने वाली जगहें) से सर्दी के लिए घास काटकर रखना होता है। मक्की की कटाई, अरबी निकाली जा रही होती है। अदरक निकाल कर बाजार पहुंचाना होता है। ऐसे अस्तव्यस्त समय के बीच दीवाली मनाने की फुरसत नहीं मिलती, इसलिए बाद में बूढ़ी दीवाली मनाई जाती है। बूढ़ी दीवाली के पहले दिन मक्की के सूखे टांडों को जलाया जाता है। ढोल करनाल, दुमालू के लोकसंगीत में गूँथी शिरगुल देव की गाथा गाई जाती है। कार्यक्रम देर रात तक चलता है। अमावस्या के मौके पर दीवाली का मुख्य नृत्य 'बूढ़ा नृत्य' होता है। हुड़क बजाते हैं। शाम को सूखी लकड़ी एकत्र कर जलाई जाती है। अगले दिन पड़वा को देव पूजा होती है।

बूढ़ी दीवाली के दिन उड़द भिगोकर फिर उसे पीसकर, नमक मसाले मिलाकर आटे के गोले के बीच भरकर पहले तवे पर रोटी की तरह सेंका जाता है फिर सरसों के तेल में फ्राई कर देसी घी के साथ खाया जाता है। मूड़ा, मक्की भूनकर व धान को नमक के पानी में कई दिन भिगोकर, छिलका अलग कर भूनकर, कूटकर चिवड़ा बनाकर खाया खिलाया जाता है। इन पहाड़ी खानों का अपना विशिष्ट स्वाद होता है। कई स्थानों पर दीवाली को मंगशराली भी कहते हैं। पुरेटुआ का गीत गाना इस अवसर पर जरूरी समझा जाता है। जिसमें वर्णित है कि त्योहार के मौके पर घर पर ही रहना चाहिए। पुरेटुआ ने अपनी वीरता के अभिमान में ऐसा किया और मारा गया। सिरमौर में कई जगह दिन में सिरमौरी लोक नाट्य सांग और स्वांग का आयोजन भी होता है। उत्सव के दौरान हर शाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम मची रहती है। आग जलाकर चारों तरफ बैठकर लोक नृत्य 'नाटी' का रंग जमता है। खलियानों में रखे कृषियंत्रों पर दीपक जलाए जाते हैं। पारम्परिक लोक गीत गाए जाते हैं। इस दीवाली को क्षेत्र में पुरानी या बूढी दीवाली के नाम से जाना जाता है। इस दिन पहाड़ी उत्पाद झंगोरे से तैयार विशेष पकवान मेहमानों को परोसे जाते हैं। इसके बाद दूसरे दिन रात्रि में मुख्य होलियात खेली जाती है, और ग्रामीण लगभग आधी रात तक अपनी लोक संस्कृति पर आधारित लोकगीतों व लोकनृत्यों पर थिरकते हुए पर्व का जश्न मनाते हैं। तीसरे दिन भिरुड़ी का आयोजन होगा। जिसमें अंतिम होलियात खेली जाएगी। चौथे दिन मुख्य भांड़ का आयोजन होता है और पांचवें दिन गावों में पांडव नृत्य के साथ पर्व को विदाई दी जाएगी। पर्व को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह बना हुआ है। दूरदराज के इलाकाकों में नौकरी कर रहे लोगों ने भी पर्व को लेकर घरों को आना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड सरकार ने इस दिन सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया हुआ है।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक महाफैसला! धारा 6 और तमिलनाडु की धारा 29-ए की दलील भी नहीं आई काम!

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं

दादा की संपत्ति पर पोते का जन्मसिद्ध दावा सुप्रीम कोर्ट ने नकारा !पिता को मिली संपत्ति अब उसकी स्वतंत्र मिल्कियत? हर परिवार और संपत्ति मालिक के लिए जानना ज़रूरी? -समग्र व्यापक महा-विश्लेषण

दादा की संपत्ति पर पोते का जन्मसिद्ध अधिकार खत्म ? सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला ! संयुक्त परिवार से लेकर अदालतों तक मचेगी फैसले की गूंज ! धारा 8 ने बदल दी पीढ़ियों से चली आ रही संपत्ति की कानूनी परिभाषा ! सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला, जिसने दादा-पोते के संपत्ति संबंधों की कानूनी तस्वीर बदल दी ! हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 की सीमा भी स्पष्ट ! पिता की विरासत पर पोते का दावा क्यों नहीं चलेगा?1986 के फैसले से 2026 तक न्यायिक सिद्धांत की निर्णायक यात्रा ! वैश्विक स्तरपर भारत की सभ्यता और पारिवारिक संस्कृति में संयुक्त परिवार व्यवस्था का सदियों से विशेष स्थान रहा है। दादा परिवार के मुखिया,पिता परिवार की जिम्मेदारियों के वाहक और पोती-पोते परिवार की भावी पीढ़ी के प्रतीक माने जाते रहे हैं।संयुक्त परिवार में संपत्ति केवल आर्थिक संसाधन नहीं,बल्कि पीढ़ियों की विरासत,पारिवारिक सम्मान और आपसी विश्वास का प्रतीक भी रही है।लेकिन बदलते सामाजिक परिवेश, डिजिटल युग की नई पीढ़ी की स्वतंत्र सोच,पारिवारिक हस्तक्षेप, संपत्ति के बढ़ते बाजार मूल्य और आपसी मतभेदों के कारण संयुक्त परिवारों में संपत्ति विवाद लगातार कानूनी चुनौती बनते जा रहे हैं।अनेक विवाद निचली अदालतों से होते हुए उच्च न्यायालयों और अंततः सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच रहे हैं। इसी महत्वपूर्ण कानूनी परिप्रेक्ष्य में मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र बताना चाहूंगाकि 6 नवंबर 2026 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसा फैसला सुनाया है,जिसने दादा से पिता को विरासत में मिली संपत्ति पर पोते के जन्मसिद्ध अधिकार के सवाल को नई कानूनी स्पष्टता प्रदान की है।अदालत ने स्पष्ट किया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अंतर्गत पिता को प्राप्त संपत्ति केवल इस कारण संयुक्त हिंदू परिवार की पैतृक संपत्ति नहीं बन जाती कि वह उसके पिता अर्थात पोते के दादा से विरासत में मिली हैइस फैसले का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह परिवारों में संपत्ति के स्वामित्व, उत्तराधिकार और सहदायिकी अधिकारों के बीच अंतर को समझने का अवसर देता हैइस ऐतिहासिक निर्णय का नाम है जे .राजेश (माइनॉर) थ्रू हिज मदर एंड नेचुरल गार्डियन जे.गोमाथी वर्सेज. एम.कुमारण(डेड) थ्रू एलआर एस एंड ऑर्दर्स ।न्यूट्रल साइटेशनः2026आइएनएससी 1208 अपील संख्याः सिविल अपील नों. 7020 श्रद्ध 2012 पीठःन्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह एवं न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, निर्णय लिखने वाली न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल परिणाम : अपील खारिज,मद्रास हाईकोर्ट का निर्णय बरकरारयह निर्णय केवल किसी एक परिवार के संपत्ति विवाद का निपटारा नहीं है,बल्कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत विरासत में मिली संपत्ति और पारंपरिक सहदायिकी संपत्ति के बीच अंतर को पुनः स्थापित करता है। इस मामले में अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल संपत्ति का मूल स्रोत दादा होना, उसे पोते के लिए स्वतः जन्मसिद्ध अधिकार वाली संपत्ति नहीं बना देता। सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्रकार की पैतृक संपत्ति में पोते का अधिकार समाप्त नहीं किया है। निर्णय का वास्तविक केंद्र धारा 8 के अंतर्गत प्राप्त व्यक्तिगत विरासत और संयुक्त सहदायिकी संपत्ति के बीच कानूनी अंतर है। साथियों बात अगर हम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 का असली अर्थ क्या है? इसको समझने की करें तो,इस फैसले की सबसे महत्वपूर्ण कानूनी धुरी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 है। यह धारा उस स्थिति में लागू होती है जब किसी हिंदू पुरुष की मृत्यु बिना वसीयत किए हो जाती है। ऐसी स्थिति में उसकी संपत्ति कानून में निर्धारित उत्तराधिकारियों के क्रम के अनुसार हस्तांतरित होती है। इसमें प्रथम श्रेणी अर्थात क्लास-द्ध के उत्तराधिकारियों में पुत्र, पुत्री, विधवा और माता सहित अन्य निर्धारित उत्तराधिकारी शामिल हैंयहां एक महत्वपूर्ण कानूनी अंतर समझना आवश्यक है। यदि मृतक का पुत्र जीवित है तो उसका पुत्र अर्थात पोता केवल इस रिश्ते के आधार पर क्लास-द्ध का प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी नहीं बन जाता। लेकिन यदि पुत्र की मृत्यु पिता अर्थात दादा से पहले हो चुकी है, तो पूर्वमृत पुत्र का बेटा निर्धारित उत्तराधिकार के अंतर्गत हिस्सा प्राप्त कर सकता हैसर्वोच्च न्यायालय ने इसी अंतर को रेखांकित किया। अदालत के अनुसार, जब दादा की संपत्ति धारा 8 के अंतर्गत उसके क्लास-द्ध उत्तराधिकारियों को मिल जाती है,तो प्रत्येक उत्तराधिकारी अपने हिस्से का स्वतंत्र मालिक बनता है। धारा 19 के अनुसार ऐसे उत्तराधिकारी सामान्यतः हिस्सेदार के रूप में संपत्ति प्राप्त करते हैं, न कि एक निरंतर संयुक्त सहदायिकी के रूप में।इसलिए पिता को मिला हिस्सा केवल इस आधार पर संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति नहीं बन जाता कि उसका मूल स्रोत दादा की संपत्ति थी। पिता को अपने हिस्से पर स्वतंत्र स्वामित्व प्राप्त होता है। साथियों बात अगर हम वर्ष 1986 का ऐतिहासिक फैसला इस मुकदमे में क्यों बना सबसे बड़ा आधार? को समझने की करें तो, इस पूरे विवाद को समझने के लिए वर्ष 1986 का एक महत्वपूर्ण निर्णय जानना आवश्यक है। वह है कमिश्नर ऑफ़ वेल्थ टैक्स,कानपुर बनाम चन्दर सेंन,(1986) 3 एससीसी 567।इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कानूनी सिद्धांत स्थापित किया था कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत पिता से विरासत में मिली संपत्ति पुत्र को उसकी व्यक्तिगत हैसियत में प्राप्त होती है, न कि अनिवार्य रूप से उसके अपने हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता के रूप में।इसका अर्थ यह है कि पारंपरिक हिंदू कानून में जन्म से सहदायिकी अधिकार की जो अवधारणा थी, उसे धारा 8 के तहत उत्तराधिकार से प्राप्त प्रत्येक संपत्ति पर स्वतः लागू नहीं किया जा सकता।इसके बाद युधिशटर बनाम अशोक कुमार ,(1987) 1 एससीसी 204 में भी चंदर सेन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। वर्तमान मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इन पुराने निर्णयों के साथ अन्य प्रासंगिक फैसलों का भी अध्ययन किया और स्पष्ट किया कि संहिताबद्ध उत्तराधिकार कानून को नजरअंदाज करके पुराने व्यक्तिगत हिंदू कानून के आधार पर पोते का जन्मसिद्ध दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता।यही इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी पक्ष है। न्यायालय ने 1986 के सिद्धांत को कोई नया कानून बनाकर नहीं, बल्कि वर्तमान विवाद के तथ्यों पर लागू करके उसकी प्रासंगिकता को फिर से सटीकता से रेखांकित किया।

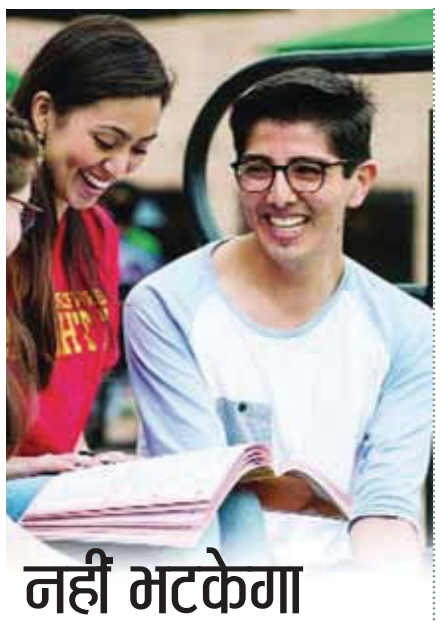
साथियों बात अगर हम सुप्रीम कोर्ट ने धारा 6 औरतमिलनाडु की धारा 29- ए की दलील क्यों खारिज की? इसको समझने की करें तो इस मुकदमे में अपीलकर्ता की ओर से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 और तमिलनाडु में लागू धारा 29-ए का भी सहारा लिया गया था। अपीलकर्ता का तर्क था कि उसका जन्म 6 जनवरी 1994 को हो चुका था और समझौता डिक्री 3 फरवरी 1994 को पारित हुई थी।इसलिए उसे जन्म से सहदायिकी अधिकार प्राप्त हो चुका था।लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया।धारा 6 का संबंध मिताक्षरा संयुक्त हिंदू परिवार की सहदायिकी संपत्ति में अधिकार के उत्तराधिकार से है। वर्ष 2005 के संशोधन ने बेटियों को भी बेटों के समान जन्म से सहदायिकी अधिकार प्रदान किए। वहीं तमिलनाडु की धारा 29-ए के अंतर्गत भी निर्धारित शर्तों के अधीन बेटियों को सहदायिकी अधिकार दिए गए थेन्यायालय ने कहा कि इस मामले में दादा की मृत्यु के बादउत्तराधिकार पहले ही खुल चुका था और संपत्ति क्लास-I उत्तराधिकारियों में चली गई थी। इसके बाद 1994 में हुए समझौते के तहत अलग- अलग हिस्से निर्धारित हो गए। इसलिए अपीलकर्ता दादा की मृत्यु के समय जीवितसहदायी नहीं था और उसके पक्ष में धारा 6 अथवा तमिलनाडु की धारा 29-ए लागू नहीं की जा सकती।

इंदिरा गांधीः जिनके फैसलों ने बदल दी भारत की राजनीतिक तस्वीर

योगेश कुमार गोयल

पं. जवाहरलाल नेहरू के घर 19 नवम्बर 1917 को जब प्रियदर्शिनी नामक कन्या ने जन्म लिया था तो किसे पता था कि यही कन्या आगे चलकर न केवल इस देश की बागडोर संभालेगी बल्कि अपनी दबंगता से पूरी दुनिया में मिसाल बन जाएगी। ऑक्सफोर्ड और स्विट्जरलैंड में उच्च शिक्षा प्राप्ति के पश्चात् इंदिरा गांधी ने उच्च पद पर नौकरी करने या कोई अन्य कार्य करने के बजाय अपना जीवन देशसेवा में समर्पित करने का निश्चय किया। देशभक्ति की भावना इंदिरा जी में बचपन से ही कूट-कूटकर भरी थी। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आव्हान से प्रेरित होकर बचपन में ही इन्होंने अपने घर के बाहर अपने कीमती कपड़ों की होली जलाकर न केवल अपनी इसी भावना का परिचय दिया था बल्कि उसके बाद इंदिरा जी से प्रेरणा लेकर इस आन्दोलन ने पूरे देश में जोर पकड़ा था। इंदिरा जी के स्कूली दिनों में एक दिन स्कूल में गांधी जी के आमरण अनशन को लेकर एक सभा का आयोजन था, जिसमें बच्चों को भी बोलने का अवसर दिया गया था। जब इंदिरा जी ने बोलना शुरू किया तो सभागार में सन्नाटा छा गया और सभी एकटक इंदिरा को निहारने लगे कि इतनी छोटी बालिका इतनी गूढ़ बातें कैसे कर रही है। उन्होंने कहा, ''आखिर स्वर्ण अपने ही दलित भाईयों को गिरा हुआ, छूत और निकृष्ट क्यों समझते हैं तथा उनके साथ दुर्व्यवहार और अत्याचार क्यों करते हैं? अगर हमने अपनी ही सेवा करने वालों का इस तरह से निरन्तर तिरस्कार न किया होता तो आज अंग्रेजों को इस प्रकार लाभ उठाने का अवसर न मिल रहा होता और न ही बापू को इस तरह से आमरण अनशन कर अपने प्राण दांव पर लगाने पड़ते।'' इंदिरा जी की इन गूढ़ और तर्कसम्मत बातों के समक्ष सभी नतमस्तक थे और उनकी सराहना कर रहे थे। इंदिरा में बचपन से ही एक अच्छी राजनेता होने के तमाम गुण विद्यमान थे। 21 वर्ष की आयु में वह कांग्रेस में शामिल होकर सक्रिय राजनीति में कूद पड़ी। उसके बाद उन्होंने आजादी के आन्दोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। 1942 में उन्होंने फिरोज गांधी से प्रेम विवाह किया किन्तु 1960 में फिरोज गांधी का अकस्मात् निधन हो गया। पिता जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद देश की बागडोर संभालने की जिम्मेदारी इंदिरा के कंधों पर आई तो अपनी दृढ़ता, दबंगता, निडरता और वाकपटुता से उन्होंने दुनियाभर को अपना लोहा मानने को विवश कर दिया। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित एवं प्रभावशाली देशों में भी उनकी तूती बोलती थी। 1966 से 1977 तक उन्होंने देश पर एकछत्र शासन किया और उनकी कार्यशैली तथा देश के प्रति उनका समर्पण भाव देखकर विरोधी भी उनकी सराहना किए बिना नहीं रह पाते थे। हालांकि लालबहादुर शास्त्री के बाद प्रधानमंत्री बनी इंदिरा को शुरूआती दौर में 'गूंगी गुड़िया' की उपाधि दी गई थी किन्तु बहुत ही कम समय में अपने साहसिक निर्णयों से इंदिरा ने साबित कर दिखाया था कि वो एक 'गूंगी गुड़िया' नहीं बल्कि 'लौह महिला' हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण तथा 1971 के भारत-पाक युद्ध में भारत की शानदार जीत के बाद इंदिरा जी जनमानस की आंखों का तारा बन गई थी किन्तु 1975-77 के आपातकाल ने उनकी छवि पर ग्रहण लगाने में प्रमुख भूमिका निभाई और उस दौर ने उनकी छवि एक तानाशाह के रूप में स्थापित कर दी। यही वजह रही कि 1977 में इंदिरा को पहली बार हार का सामना करना पड़ा और सत्ता उनके हाथ से छिन गई किन्तु निराश होना तो जैसे उन्होंने सीखा ही नहीं था, इसलिए 1980 में एक बार फिर विशाल बहुमत के साथ वह सत्ता में लौटी। अपने शासनकाल में उन्होंने कभी अलगाववादी व साम्प्रदायिक आग भड़काने वाले तत्वों को नहीं पनपने दिया। ऐसे तत्वों को उन्होंने बेदर्दी से कुचलने में जरा भी देर नहीं लगाई। 1980 में पुनः देश का शासन संभालने के बाद पंजाब में अलगाववादी ताकतों ने खालिस्तान की मांग शुरू की और दूसरे देशों की शह पर अपने नापाक इरादों को सफल बनाने के लिए सिख अलगाववादियों ने भयानक नरसंहार का दौर शुरू किया तथा पंजाब में अवैध रूप से हथियारों के जखीरे इकट्ठा करने शुरू कर दिए। देश की जांबाज, निडर एवं साहसी नेता इंदिरा को भला यह कैसे सहन होता, इसलिए जैसे ही उन्हें खबर मिली कि सिख अलगाववादियों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर जैसी पाक जगह में भी हथियारों का विशाल जखीरा इकट्ठा किया है तो उन्हें देश की एकता और अखंडता कायम रखने तथा अलगाववादियों के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए इस पवित्र धर्मस्थल के भीतर न चाहते हुए भी 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' के तहत पुलिस भेजने का सख्त निर्णय लेना पड़ा। हालांकि उस वक्त स्वर्ण मंदिर के भीतर पुलिस बल भेजने के उनके फैसले की बहुत आलोचना हुई किन्तु जब स्वर्ण मंदिर से हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा बरामद हुआ और धार्मिक स्थल की आड़ में चल रही इस राष्ट्र विरोधी साजिश का भंडाफोड़ हुआ तो उन्हीं लोगों ने इंदिरा जी की सराहना भी की। उसके बाद इंदिरा ने जिस दिलेरी और दृढ़ता के साथ अलगाववादियों को रौंदा, वह एक मिसाल बन गया लेकिन अलगाववादियों के विरूद्ध चलाए गए उनके इसी ऑपरेशन की वजह से ही वह उनकी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर आ गई, जिन्होंने हर हाल में उनकी हत्या कर उन्हें अपने मार्ग से हटाने की ठान ली।

इंदिरा जी को स्वयं अपनी मौत का आभास पहले ही हो गया था लेकिन फिर भी वह अपने दृढ़ इरादों से टस से मस न हुई और अलगाववादियों के खिलाफ अपना अभियान पहले से भी तेज कर दिया। 30 अक्तूबर 1984 को भुवनेश्वर की एक विशाल ज



नहीं भटकेगा पढ़ाई से मन, इन टिप्स को अपनाएं

इसमें कोई दो राय नहीं कि पढ़ाई से मन आसानी से भटक जाता है और एकाग्रता की कमी बडी समस्या बन जाती है। एकाग्रता यानी आप अपने मन और दिमाग को बाकी चीजों से दूर कर एक समय में एक ही जगह लगाए। लेकिन यह बहुत मुश्किल काम है। आप अपने आसपास की चीजों से प्रभावित होते ही है। वहीं छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान लगाना और ज्यादा कठिन हो जाता है। इससे तनाव भी बढ़ जाता है। एकाग्रता बढ़ाना बहुत आसान तो नहीं लेकिन अगर आप निश्चय कर लें तो यह संभव है। यहां हम ऐसे टिप्स बता रहे हैं जिससे आप एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं और किसी भी तरह के तनाव से दूर रहे सकते हैं

- आप मन-मस्तिष्क के लिए आसपास का माहौल बहुत महत्वपूर्ण होता है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए माहौल अच्छा होना जरूरी है जिससे आपका मन भटकने से बचता है। इसलिए यही कोशिश करें कि आप पढ़ाई के लिए आरामदायक और शांतिपूर्ण माहौल चुने।
- पहली बार तो यह है कि अगर आप पढ़ाई करने बैठे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या पढ़ाना चाह रहे हैं। इसके लिए पहले से ही अपनी पढ़ाई का खाका तय कर लें। इससे आपके मन में और कोई विचार नहीं आएगा और आपका मन पढ़ाई में लगेगा।
- एकाग्रता में सबसे ज्यादा दखल विचारों की होती है। मन के भटकने का एक कारण विचारों की अधिकता भी है। इसलिए जब पढ़ाई करने समय आपको लगे कि आपके दिमाग में दूसरी चीजें आ रही हैं तो इस बात को लेकर सजग हो जाएं कि आपको अपना ध्यान नहीं भटकाना है। एक बार आप इस बात को लेकर कांशस हो जाएंगे तो एकाग्र होने में मदद मिलेगी।
- अगर आप पढ़ाई के लिए एकाग्र मन चाहते हैं तो जरूरी है कि आपकी स्टडी प्लॉन्ड हो। अगर आप योजना के साथ पढ़ाई करने बैठेंगे तो आसानी होगी। इससे आपकी पढ़ाई और समय के बीच एक अच्छा संतुलन बन जाता है और आप अपनी पढ़ाई पर ज्यादा गंभीरता से ध्यान दे पाते हैं।
- मन तब ज्यादा भटकता है जब आप एक जगह नहीं बैठते। इसलिए एकाग्र मन के लिए आपको बैठने की एक जगह सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। यह दृढ़ हो जाए कि आप अपनी पढ़ाई पूरी किए बिना सीट से नहीं उठेंगे।
- बहुत जरूरी है कि आप जहां भी बैठे हो वहां साफ-सफाई होनी चाहिए। अगर वहां बिखराव होगा तो आपका मन भी भटकेगा और ध्यान नहीं लगा पाएंगे।
- एक बहुत जरूरी टिप यही है कि आपको पहले तो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। अच्छा व्यायाम और पौष्टिक आहार न केवल आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है बल्कि आपके शरीर को भी स्वस्थ रखता है। इससे शरीर से आलस और थकान दूर होती है।



कजाकिस्तान में एमबीबीएस करना सबसे अच्छा और सबसे सस्ता विकल्प है

हर साल भारत का करीब 25 हजार युवा छात्र विदेश की टॉप यूनिवर्सिटीज के एमबीबीएस प्रोग्राम्स में एडमिशन लेते हैं। क्योंकि भारत में काउंसिलिंग प्रोसेस पूरा होने के बाद अधिकतर छात्रों, जिनको भारत में सीट नहीं मिलती है वह विदेशी यूनिवर्सिटी का रुख करते हैं।

हर साल भारत का करीब 25 हजार युवा छात्र विदेश की टॉप यूनिवर्सिटीज के एमबीबीएस प्रोग्राम्स में एडमिशन लेते हैं। क्योंकि भारत में काउंसिलिंग प्रोसेस पूरा होने के बाद अधिकतर छात्रों, जिनको भारत में सीट नहीं मिलती है वह विदेशी यूनिवर्सिटी का रुख करते हैं। जून-जुलाई में विदेशी यूनिवर्सिटीज की एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जो बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से चलती रहती है। वहीं इस साल भी विदेश से एमबीबीएस करने के लिए भारत से बड़ी संख्या में छात्रो ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है।

वहीं बाकी के छात्र एमबीबीएस काउंसिलिंग पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। भारत में आई अनिश्चितता से अंतराष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज एडमिशन प्रोसेस की डेट्स में बदलाव नहीं करेंगे। इसलिए भारत में नीट परीत्रा पास कर चुके छात्रों के पास अब एक ही ऑप्शन बचा है कि वह एमबीबीएस काउंसिलिंग राउंड में हिस्सा लेकर विदेशी यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस के लिए अपनी सीट आरक्षित करें। इससे अगर आपको भारत में सीट नहीं मिली तो कम से कम आपका साल बर्बाद नहीं होगा और विदेश में एमबीबीएस के लिए सीट मिल जाएगी। क्योंकि कजाकिस्तान, जॉर्जिया, चीन और रूस आदि देशो में अधिकतर यूनिर्वसिटी वीजा जारी करने से पहले ट्यूशन फीस का भुगतान नहीं लेतीं।

विदेश में एमबीबीएस

हर मेडिकल स्टूडेंट को नेशनल एग्जिट टेस्ट देना अनिवार्य है। इसका मतलब यह हुआ कि भले ही आप एम्स में पढ़ाई कर रहे हों, या किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी में या फिर विदेश से स्नातक हों। प्रैक्टिस करने का लाइसेंस पाने के लिए सभी डॉक्टरों को भारत में NExT लाइसेंस परीक्षा पास करनी होगी। NMC भारत और विदेश से स्नातक करने वालों को एक समान मानता है। ऐसे में भारत में प्रबंधन/एमबीबीएस सीटों के लिए छात्र भारी फीस क्यों चुकाए। क्योंकि भारत में 1 करोड़ रुपए लागत वाली सीट भी प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस नहीं दे सकती है। ऐसे में यहां पर सरकारी सीट के लिए एमसीसी काउंसलिंग से गुजरने और विदेश में कम फीस वाले शीर्ष रैंक कॉलेज में अपनी सीट आरक्षित करने के ऑप्शन को चुनना चाहिए।

जल्दबाजी में न लें एडमिशन

एडमिशन लेना सिर्फ आधे काम को पूरा करना है। स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम के अंत में जब स्टूडेंट वापस भारत आता है, तो उनको FMGE की जगह NExT की परीक्षा देनी होती है। पिछले 10 सालों में लाइसेंस परीक्षा FMGE के रिजल्ट परिणाम साफ दिखाते हैं कि एमबीबीएस में एडमिशन लेने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन असल समस्या बाहर निकलने के बाद है। हालांकि स्थानीय सलाहकार छात्रों को सिर्फ एमबीबीएस में प्रवेश प्रदान करते हैं, बाहर निकलने का कोई समाधान नहीं है। ऐसे में आपको उन पेशेवर प्रदाताओं के पास जाने की जरूरत है, तो न सिर्फ आपको एडमिशन दे सकते हैं, बल्कि आपको NExT/USMLE जैसी लाइसेंस परीक्षाओं में मंजूरी की गारंटी भी दे सकते हैं।

कजाकिस्तान की कोक्शेताउ स्टेट यूनिवर्सिटी

कजाकिस्तान में एमबीबीएस के लिए कोक्शेताउ स्टेट यूनिवर्सिटी एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है, जो भारतीय छात्रों के लिए एकीकृत NExT बैच के कारण भारत में लाइसेंस के लिए गारंटी प्रदान करता है। वर्तमान समय में इस यूनिवर्सिटी में करीब 1,000 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं यहां पर NExT में 100% उत्तीर्ण अनुपात के साथ ही सफलता की वजह एमबीबीएस कोर्स में एकीकृत 6 साल की NExT कोचिंग है। यह यूनिवर्सिटी पहले साल से ही छात्रों को NExT की तैयारी करवाना शुरू कर देती है। वहीं हर सेमेस्टर के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा उनका मूल्यांकन किया जाता है। यूनिवर्सिटी में पहले 150 स्टूडेंट्स को 100% स्कॉलरशिप के साथ यह पाठ्यक्रम प्रदान किया जाता है।

बता दें कि अगर आपका नीट स्कोर 500 से कम है, और एमबीबीएस कोर्स का बजट 40 लाख से रुपए से कम है। तो आपको प्लान बी के तहत विदेश से एमबीबीएस करना चाहिए। वरना आप NEET में फिर से एग्जाम देकर अपना एक साल और बर्बाद करेंगे।

आपको किसी ऐसे एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लेना चाहिए, जो NExT/USMLE जैसी लाइसेंसी परीक्षाओं के लिए छात्रों को न तैयार करता हो। क्योंकि बिना लाइसेंस के भारत में डॉक्टर बनने की संभावना बेहद कम है। अगर आप न्यूरोलॉजिस्ट, त्वचा रोग विशेषज्ञ या हृदय रोग विशेषज्ञ आदि बनना चाहते हैं, तो आपको शुरूआत से ही USMLE की तैयारी करनी चाहिए।

वर्तमान समय में देखा जाए तो कजाकिस्तान में एमबीबीएस करना सबसे अच्छा और सबसे सस्ता विकल्प है। आप कजाकिस्तान के शीर्ष रैंक वाले सरकारी कॉलेज कोक्शेताउ स्टेट यूनिवर्सिटी में इंटीग्रेटेड एनईएक्सटी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। यहां पर आप NExT की भी तैयारी कर लेंगे। भारत से पहले 150 आवेदकों को इस यूनिवर्सिटी में NExT कोचिंग निःशुल्क यानी की फी में कराई जाती है। वहीं अगर आपका बजट अधिक यानी की 45 लाख रुपए के आसपास है। तो आप जॉर्जिया में एमबीबीएस, संयुक्त राज्य अमेरिका में पीजी के लिए जॉर्जिया विश्वविद्यालय में एकीकृत अमेरिकी कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं।





जबरदस्त करियर का नया रास्ता, मैनेजमेंट में करें पीएचडी

प्रबंधन यानी मैनेजमेंट में पीएचडी छात्रों के बीच लोकप्रिय ऑप्शन है। यह एक प्रतिष्ठित डिग्री आपका प्रोफेशनल प्रोफाइल बेहतर बनाती है। इंडस्ट्री और शिक्षा क्षेत्र में लीडरशिप रोल के लिए इसमें कई बेहतर मौके मौजूद हैं। अगर करियर में सुधार चाहते हैं तो यह डिग्री आपके लिए सही हो सकती है। बिजनेस और मैनेजमेंट की दुनिया में आजकल ज्यादा पढ़ाई करना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैनेजमेंट में पीएचडी करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह कोर्स अपने क्षेत्र के बारे में गहरी जानकारी देता है। अगर आप ऐसे में भविष्य में कामयाब होना चाहते हैं, तो मैनेजमेंट पीएचडी करना आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। मैनेजमेंट में पीएचडी करने के बाद आपके पास बहुत सारे अच्छे जॉब के मौके होंगे। मैनेजमेंट पीएचडी करके छात्र अपनी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर, पॉलिसी एनालिस्ट, स्ट्रेटेजिक मैनेजर, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, चीफ एक्जीक्यूटिव, ऑफिसर, क्वांटिटेटिव एनालिस्ट और बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर जैसे पदों पर काम कर सकते हैं। यह डिग्री आपको पढ़ाने और नौकरी, दोनों ही क्षेत्रों में काम करने का मौका देती है और जॉब की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मैनेजमेंट पीएचडी कोर्स पूरी दुनिया में मान्य है और आप बड़ी-बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने के लिए योग्य बन जाते हैं। इस कोर्स से आप एक अच्छे विचारक, समस्याओं का हल निकालने वाले, बेहतर निर्णय लेने वाले और कुशल योजनाकार बनते हैं। इसके साथ आप मैनेजमेंट, काम सौंपने, बातचीत करने और मुश्किल व्यावसायिक परिस्थितियों को संभालने में भी माहिर बनते हैं।

बढ़ रही है मैनेजमेंट में पीएचडी की मांग

दुनियाभर में उथल-पुथल के बाद दुनिया ने ऐसे लीडर्स की जरूरत महसूस की जो मुश्किल समय में भी सही फैसले ले सकें। मैनेजमेंट में पीएचडी से न सिर्फ छात्र, बल्कि उन कंपनियों को भी फायदा मिलता है जिन्हें अनिश्चित समय में नेतृत्व करने वाले कर्मचारियों की जरूरत है और नए जमाने की प्रतिभा रणनीतियों को लागू कर सकें।

शोध और नवाचार

पीएचडी प्रोग्राम शोध और नवाचार को बढ़ावा देते हैं। स्टूडेंट्स को नए विचारों पर काम करने, नई रणनीतियां बनाने के साथ मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपने ज्ञान का योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आज के समय की व्यावसायिक चुनौतियों का सामना करने और प्रगति करने के लिए रिसर्च करना बहुत जरूरी है।

शैक्षणिक संस्थानों और इंडस्ट्री के बीच सहयोग

ज्यादातर मैनेजमेंट पीएचडी प्रोग्राम शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों के बीच सहयोग पर जोर देते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि छात्रों को प्रैक्टिकल जानकारी और असल दुनिया का अनुभव दोनों मिलें, जिससे उनकी रिसर्च प्रासंगिक और प्रभावशाली बने। इससे थ्योरी ज्ञान और प्रैक्टिकल उपयोग के बीच की खाई को पाटने में भी मदद मिलती है।

क्या पीएचडी करना आपके लिए सही है?

पीएचडी में दाखिला लेने से पहले, यह सोचने की जरूरत है कि क्या यह आपके करियर के लक्ष्यों के हिसाब से सही है। पीएचडी प्रोग्राम काफी कठिनाई भरे हो सकते हैं। इसके लिए पूरी लगन और रिसर्च के प्रति जुनून की जरूरत होती है। अगर आप हमेशा खुद को बेहतर बनाते रहने और करियर को आगे बढ़ाने में यकीन करते हैं, तो मैनेजमेंट में पीएचडी आपके लिए सटीक कदम है। मैनेजमेंट में पीएचडी धीरे-धीरे छात्रों के बीच लोकप्रिय हुआ है। यह प्रतिष्ठित डिग्री आपके प्रोफेशनल प्रोफाइल को बेहतर बनाती है। आज के समय में, जब कंपनियां अच्छी तरह से प्रशिक्षित लोगों की तलाश कर रही हैं, तब यह डिग्री अच्छी नौकरियां व करियर में तरक्की दिलाने में सक्षम है।



नई टेक्नोलॉजी के आने से तेजी से विकसित हुई है भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री

भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने देश की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, इसे देश के सबसे पुराने इंडस्ट्री में से एक माना जाता है। भारत में पहले सिर्फ फैब्रिक प्रोडक्शन किया जाता था, लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी के आने से यह तेजी से विकसित हुई है।

किसी भी देश व सभ्यता के विकास में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान होता है। भारत में भी यह इंडस्ट्री देश की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, इसे देश के सबसे पुराने इंडस्ट्री में से एक माना जाता है। भारत में पहले सिर्फ फैब्रिक प्रोडक्शन किया जाता था, लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी के आने से यह तेजी से विकसित हुई है। अब यह इंडस्ट्री रिसर्च, डेवलपमेंट, मेन्युफैक्चरिंग और मर्केंडाइजिंग जैसी कई श्रेणियों में काम कर रही है। जिसके कारण इसमें जॉब के अवसर भी पहले की अपेक्षा अब तेजी से बढ़ रहे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में रंग, वस्त्र फाइबर, मशीनरी और उत्पाद, कपड़ा और परिधान प्रक्रियाओं को डिजाइन और नियंत्रित करने की प्रक्रिया शामिल है। जिसमें फैशनेबल कपड़ों की मांग को ध्यान में रखते हुए, बहुत ज्यादा रिसर्च, क्रिएटिविटी और इनोवेशन की जरूरत होती है। इसमें टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की यह शाखा उन सिद्धांतों का भी अध्ययन करती है जो कपड़ा फाइबर के निर्माण में पॉलिमर का विश्लेषण करते हैं। जिनका उपयोग सभी प्रकार के यार्न और टेक्सटाइल कपड़ों के निर्माण में किया जाता है। कपड़ा इंजीनियरिंग में, कपड़े को आकर्षक और फैशनेबल बनाने पर जोर दिया जाता है। इसके लिए टेक्सटाइल इंजीनियर को काफी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। टेक्सटाइल इंजीनियर को नवाचार, अनुसंधान और रचनात्मकता जैसे कौशल की आवश्यकता होती है।

किस तरह का कोर्स करें

अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी जैसे विषय में पढ़ाई करनी होगी। इसके बाद टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में बीई या बीटेक, टेक्सटाइल डिजाइनिंग में बीए, टेक्सटाइल डिजाइन में बीएससी, बैचलर ऑफ डिजाइन, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल मेन्युफैक्चर या टेक्सटाइल केमिस्ट्री में बीटेक कर सकते हैं। वहीं आप इन कोर्सेज में एडवांस्ड डिप्लोमा, एमईए एमटेक और उसके बाद पीएचडी भी कर सकते हैं।

जॉब प्रोफाइल क्या है

टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप कई जॉब प्रोफाइल पर रहकर कार्य कर सकते हैं। जिसमें मुख्य रूप से प्रोडक्शन कंट्रोल, प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग प्रोसेस, सेल्स, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, सुपरविजन आदि डिपार्टमेंट्स में काम कर सकते हैं। एक टेक्सटाइल इंजीनियर आम तौर पर इंजीनियरिंग प्रोसेस से जुड़ा होता है, जबकि अपैरल और गारमेंट्स की डिजाइनिंग और मेन्युफैक्चरिंग के लिए काम करने वाले प्रोफेशनल्स प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके अंदर कई स्किल का होना जरूरी है। जिसमें मुख्य रूप से कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्प्यूटर स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी जरूरी हैं। इसके अलावा उनमें चीजों की बारीकियों पर ध्यान देने की क्षमता, लॉजिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी होनी भी जरूरी है।

करियर की संभावनाएं

इस क्षेत्र में करियर की अपार संभावनाएं है। कोर्स पूरा होने के बाद आप टेक्सटाइल मिल्स, एक्सपोर्ट हाउसेज, निटवेयर मेन्युफैकचरिंग यूनिट्स, टेक्सटाइल डाइंग एंड प्रिंटिंग यूनिट्स में काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा निजी सिल्क, हैंडलूम, जूट, खादी, क्राफ्ट डेवलपमेंट संस्थानों में काम कर सकते हैं। आप फैशन रीटेलर्स डिजाइन स्टूडियोज और बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जैसे में भी काम कर सकते हैं।

सैलरी

टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा व डिग्री के बाद आप फ्रेशर के तौर पर अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो 30 से 45 हजार रूपये का शुरुआती वेतन आसानी से मिल जाता है। अनुभव के बाद, आप प्रति माह 50 हजार से एक लाख तक कमा सकते हैं। अगर आपने आईआईटी से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है, तो आपको शुरुआती वेतन काफी आकर्षक लग सकता है।

दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वालों की खैर नहीं, धूल से धुएं तक हर मोर्चे पर बढ़ेगी सख्ती

नई दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निगरानी और कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से सड़क की धूल, निर्माण कार्यों और वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर विशेष नजर रखने को कहा है। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली कैबिनेट ने मंगलवार को प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) जांच केंद्रों को आधुनिक बनाने के लिए पांच करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदूषण के खिलाफ अभियान में न तो काम की रफ्तार कम होगी और न ही कार्रवाई में कोई ढिलाई बरती जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को शास्त्री पार्क स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) में प्रदूषण की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की। इसमें पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, परिवहन मंत्री डॉ.



पंकज कुमार सिंह और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में शहर की वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए चलाए जा रहे प्रयासों और प्रदूषण के स्रोतों पर नियंत्रण को लेकर चर्चा हुई।

बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ सरकार की लड़ाई पूरी ताकत से जारी है और अब कार्रवाई को और तेज किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदूषण फैलाने वाले सभी प्रमुख स्रोतों की निगरानी बढ़ाई जाए। इसमें सड़कों से उड़ने वाली धूल, निर्माण स्थलों से निकलने वाला प्रदूषण और वाहनों से निकलने वाला धुआं शामिल है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई करने को भी कहा गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली कैबिनेट ने मंगलवार को प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) जांच केंद्रों को आधुनिक बनाने के लिए पांच करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। सरकार का उद्देश्य इन केंद्रों की व्यवस्था को बेहतर बनाना और वाहनों से होने वाले प्रदूषण की जांच को प्रभावी बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की हवा साफ करने के लिए सरकार दिन-रात काम कर रही है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, बुधवार सुबह दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 218 दर्ज किया गया। यह 'खराब' श्रेणी में आता है। CPCB के मानकों के अनुसार, 0 से 50 तक AQI अच्छा, 51 से 100 संतोषजनक, 101 से 200 मध्यम, 201 से 300 खराब, 301 से 400 बेहद खराब और 401 से 500 गंभीर श्रेणी में माना जाता है। ऐसे में दिल्ली की हवा अभी भी खराब श्रेणी में बनी हुई है।

चेन्नई की सड़कों पर उतरे 10 हजार लोग, 22 मुस्लिम कैदियों की रिहाई और आरक्षण को लेकर ये हैं मांगे

चेन्नईः चेन्नई में मुस्लिम कैदियों की रिहाई की मांग करते हुए हजारों लोग सड़क पर उतरे और प्रोटेस्ट किया. डॉ. एम. एच. जवाहरुल्लाह की पार्टी एमएमके यानी 'मनिथनेया मक्कल काची' द्वारा आयोजित एक प्रोटेस्ट में करीब 10 हजार लोगों ने हिस्सा लिया. इस प्रदर्शन में आजीवन कारावास काट रहे 22 मुस्लिम कैदियों की रिहाई और मुस्लिम धर्म अपनाने वालों के लिए 3.5 फीसदी आरक्षण को बहाल करने के वास्ते कानूनी संशोधन की मांग की गई. 22 मुस्लिम कैदियों में वे 14 दोषी भी शामिल हैं, जिन्हें 1998 के कोयंबटूर सीरियल बम धमाकों के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. इस हमले का निशाना बीजेपी नेता



के.एन.के. आडवाणी थे और इसमें 58 लोगों की जान चली गई थी. ये लोग करीब 28 साल से जेल में बंद हैं. जवाहिरुल्लाह ने बताया, 'उन्होंने (कैदी) अपनी लगभग पूरी जिंदगी जेल में बिता दी है. DMK के शासनकाल के दौरान, एक आयोग की सिफारिश पर ऐसे 41 लोगों को रिहा किया गया था, जिनमें अन्य धर्मों के लोग भी शामिल थे. पार्टी यह भी मांग कर रही है कि तमिलनाडु सरकार एक विधायी संशोधन लाए, जिससे पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों और डिनोटिफाइड कम्युनिटीज से इस्लाम अपनाने वालों के लिए 3.5 फीसदी आरक्षण को बहाल किया जा सके. चेन्नई में हुआ यह प्रोटेस्ट तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के बाद हुए सियासी बदलाव के बैकग्राउंड में हो रहा है.

SIR पर विपक्ष के आरोपों को CM धामी ने किया खारिज, UP में BJP की लगातार तीसरी जीत का जताया भरोसा

लखनऊः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्षी दलों की आपत्तियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन पर भ्रम फैलाने और राजनीतिक माहौल खराब करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने की प्रक्रिया का विरोध करने के बजाय राजनीतिक दलों को इसका समर्थन करना चाहिए. यहां उत्तराखंड महोत्सव में शामिल होने पहुंचे धामी ने संवाददाताओं से कहा कि एसआईआर देश में पहली बार नहीं हो रहा है. उन्होंने सवाल



किया कि अगर इस प्रक्रिया के जरिए मतदाता सूचियों में सुधार किया जा रहा है और एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत लोगों तथा अपात्र मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं तो इस पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए. धामी ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों को एसआईआर प्रक्रिया से अपने राजनीतिक हित प्रभावित होने की आशंका है. उन्होंने कहा कि चुनावों में लगातार हार का सामना कर रहे दल जनता के बीच अपनी स्थिति मजबूत करने के बजाय ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं, जिनसे भ्रम और असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है. उन्होंने विपक्ष पर चुनावी हार के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने का भी आरोप लगाया. उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में धामी ने विपक्षी 'इंडिया' के भाजपा को कड़ी चुनौती देने के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव से पहले विपक्षी दल अपनी मजबूती का दावा करते हैं लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद असलियत जाहिर हो जाती है. उन्होंने उत्तर प्रदेश में भाजपा की दोबारा सरकार बनने का भरोसा जताया.

धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर भारी बहुमत हासिल करेगी.

सहवाग-हेडन ओपनर, सचिन नंबर-4 और कोहली नंबर-5! मुरली विजय की ऑल-टाइम टेस्ट XI में स्पिनर को नहीं मिली जगह

नई दिल्ली। भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज मुरली विजय ने अपनी ऑल-टाइम ग्रेट टेस्ट प्लेइंग इलेवन का चुनाव किया है. जिसमें एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी नजर आ रहे हैं. ओपनर के तौर पर उन्होंने पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के साथ पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ओपनर मैथ्यू हेडन का चुनाव का चुनाव किया है. नंबर तीन के लिए उन्होंने किसी और पर नहीं बल्कि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग पर भरोसा जताया है. पोंटिंग ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं. चौथे स्थान पर उन्होंने खेल जगत



में 'क्रिकेट के भगवान' के रूप में मशहूर सचिन तेंदुलकर को रखा है. तेंदुलकर टेस्ट क्रिकेट ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.

मुरली विजय ने पांचवें स्थान पर विराट कोहली को रखा है. कोहली के बल्ले से टेस्ट क्रिकेट में 9230 रन निकले हैं. भारत की तरफ से वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज हैं. छठवें स्थान के लिए उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी पर भरोसा जताया है. धोनी बल्लेबाजी के साथ-साथ विकेटकीपिंग करने में भी महिर हैं. यही नहीं वह अपनी उम्दा कप्तानी के लिए भी दुनिया भर में मशहूर हैं.

मुरली विजय ने ऑलराउंडर के तौर पर दो खिलाड़ियों का चुनाव किया है. जिसमें सातवें स्थान पर उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव और आठवें स्थान पर पूर्व पाकिस्तानी कप्तान इमरान खान को रखा है. ये दोनों खिलाड़ी गेंद के साथ-साथ बल्ले से भी कहर ढाने के लिए मशहूर हैं. पेश तिकड़ी के तौर पर उन्होंने कर्टली एम्ब्रोस, मैलकम मार्शल और जसप्रीत बुमराह का चुनाव किया है. एम्ब्रोस ने टेस्ट क्रिकेट में 405, मार्शल ने 376 और जसप्रीत बुमराह 234 विकेट चटकाए हैं.

बक्सर से भागलपुर तक बनेगा एक्सप्रेस-वे, किसानों के लिए 11 हजार करोड़ का बैकअप

पटना। बिहार में सम्राट कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है. सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, जॉब्स और किसानों को ध्यान में रखते हुए 12 अहम फैसले लिए हैं. इनमें बक्सर से भागलपुर तक 6-लेन एक्सप्रेस-वे, पटना में 305 करोड़ का IIT रिसर्च पार्क, दरभंगा में कैंसर अस्पताल और किसानों के लिए 11,200 करोड़ की गारंटी जैसे बड़े कदम शामिल हैं.

1. बक्सर-भागलपुर 6-लेन एक्सप्रेस-वे

बक्सर से अरवल, जहानाबाद, राजगीर, सिकंदरा और मुंगेर के भीमबांध होते हुए भागलपुर तक एक नया एक्सप्रेस-वे बनेगा. आगे चलकर इसे प्रस्तावित रक्सौल हल्दिया हाईवे से भी जोड़ा जाएगा. इसका डीबीआर तैयार करने के लिए कैबिनेट ने 66.58 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. इसके निर्माण से बिहार के कई जिलों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी. साथ ही व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

2. पटना में IIT रिसर्च पार्क का निर्माण

पटना में 305 करोड़ रुपये की लागत से एक नया IIT रिसर्च पार्क बनाया जाएगा. इसके निर्माण के लिए IIT मद्रास के CUBE संस्थान को मुख्य सलाहकार और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनाया गया है. इससे बिहार के युवाओं को रिसर्च और तकनीक के क्षेत्र में नए मौके मिलेंगे.

3. दरभंगा में कैंसर अस्पताल को मंजूरी

अब मिथिलांचल के मरीजों को गंभीर इलाज के लिए दूर नहीं जाना होगा. कैबिनेट ने दरभंगा सदर अस्पताल परिसर में मुजफ्फरपुर के होमी भाभा कैंसर अस्पताल की मदद से सिर और गर्दन के कैंसर का इलाज शुरू करने की मंजूरी दे दी है.

4. IT विभाग में 124 पदों पर पक्की नौकरी

सरकारी कामकाज और ई-गवर्नेंस में तेजी लाने के लिए बिहार के आईटी विभाग में 124 स्थायी पदों पर बहाली का रास्ता साफ हो गया है. इन पदों पर प्रोजेक्ट और प्लानिंग से जुड़े काम होंगे, जिससे आम लोगों को डिजिटल सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी.

5. किसानों के अनाज के लिए 11 हजार 200 करोड़ रुपये की गारंटी

वित्तीय वर्ष 2026-27 में धान और गेहूं की खरीद बिना किसी रुकावट के चलती रहे, इसके लिए सरकार ने राज्य खाद्य आपूर्ति निगम को 11200 करोड़ रुपये के कर्ज पर सरकारी गारंटी दी है. इससे किसानों से समय पर अनाज खरीदा जा सकेगा और उन्हें उचित दाम मिलेगा.

6. जमुई और बांका में खनिजों की ई-नीलामी

बिहार में रोजगार बढ़ाने के लिए जमुई के मजोस और भंटा में लौह अयस्क (मैग्नेटाइट) और बांका के पिंडारा में तांबा, सीसा और जस्ता के ब्लॉक की ई-नीलामी को हरी झंडी दी गई है.

7. अदाणी ग्रुप को ट्रांसमिशन लाइन का जिम्मा

भागलपुर के पीरपैंती पावर प्लांट से बिजली निकालने के लिए ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का काम अदाणी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड को सौंपा गया है. कंपनी 35 साल तक इसका संचालन करेगी, जिसके बदले उत्तर और दक्षिण बिहार बिजली वितरण कंपनियां उन्हें हर साल 493.762 करोड़ रुपये का भुगतान करेंगी. 35 साल बाद यह पूरी संपत्ति मुफ्त में बिहार सरकार की हो जाएगी.

8. पानी की टंकियों और पंचायत भवनों पर सोलर पैनल

गांवों में बिजली कटने पर भी पानी की सप्लाई न रुके, इसके लिए पानी की टंकियों पर 5 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने को 48.09 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं. वहीं, सरकारी कामकाज सुचारू रखने के लिए पंचायत भवनों पर 10 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने के लिए 482.82 करोड़ रुपये का अलग बजट पास किया गया है.

9. पेंशन-छात्रवृत्ति के नियम हुए आसान

अब कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और अपार आईडी से वेरिफिकेशन बैंक खातों में आने वाली छात्रवृत्ति के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देना होगा. इसके अलावा, पंचायतों और शहरी निकायों को मिलने वाले अनुदान का ष्ट पोर्टल पर अपलोड होने के बाद, उसे अलग से महालेखाकार कार्यालय को भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

10. विधानसभा में पेश होगी ऑडिट रिपोर्ट

सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक अहम फैसला यह हुआ है कि अब अलग-अलग विभागों की ऑडिट रिपोर्ट विधानसभा और विधान परिषद में भी अनिवार्य रूप से पेश की जाएगी.

11. 7वें राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ा

स्थानीय निकायों और छात्रवृत्ति योजनाओं से जुड़े कामों को आसान बनाने के लिए 7वें राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

12. लगातार 6 साल से ड्यूटी से गायब महिला डॉक्टर बर्खास्त

मधेपुरा के रहटा स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉ. अनुराधा 17 सितंबर 2020 से लगातार बिना अनुमति ड्यूटी से गायब थीं. नोटिस का जवाब न मिलने पर राज्य मंत्रिपरिषद ने बीपीएससी की सहमति से उन्हें सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया है.

यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार कार्यकर्ता तय करेंगे BJP से किसको मिलेगा टिकट!

नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी सियासी दल तैयारी में जुटे हुए हैं. इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी भी रणनीति तैयार कर रही है. बीजेपी के टॉप नेताओं की मीटिंग में रणनीति को अंतिम रूप दिया गया है. पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन चुनावी मैदान में उतरेंगे.

इन बड़े नेताओं के कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और अगले महीने से दौरा शुरू हो जाएगा. भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने के लिए पूरी ताकत लगाने की तैयारी कर रही है. बूथ सम्मेलनों



के जरिए कार्यकर्ताओं से संपर्क साधा जाएगा. शक्ति केंद्रों के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे और गृह मंत्री अमित शाह इन सम्मेलनों को संबोधित करेंगे.

बीजेपी ने तैयारी की है कि उत्तर प्रदेश के सभी छह इलाकों में 'जन आशीर्वाद यात्रा' निकाली जाएगी. ब्रज, पश्चिम, कानपुर-बुंदेलखंड, काशी, अवध और गोरखपुर क्षेत्रों में यह यात्रा निकाली जाएगी. यात्राओं की कमान राज्य के सीनियार नेता संभालेंगे. सभी यात्राओं का समापन लखनऊ में एक बड़ी रैली करके किया जाएगा, जिसे पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित कर सकते हैं.

दिल्ली से आगरा डेढ़ घंटे में... 1123 करोड़ के कॉरिडोर को मंजूरी, मथुरा-आगरा से फरीदाबाद-पलवल तक हाईस्पीड कनेक्टिविटी

नई दिल्लीः नितिन गडकरी ने दिल्ली-आगरा कॉरिडोर पर 1,123 करोड़ रुपये और पश्चिमी दिल्ली में 359 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है. इसके तहत उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा जिले के साथ हरियाणा के फरीदाबाद और पलवल में तीन ओवर ब्रिज, चार फ्लाईओवर और चार अंडरपास बनाए जाएंगे. इससे दिल्ली से आगरा का सफर डेढ़ घंटे से भी कम वक्त में तय हो पाएगा. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को इसकी घोषणा की. गडकरी ने दिल्ली के लिए भी 360 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी.

गडकरी ने बताया कि दिल्ली-



आगरा रूट में नेशनल हाईवे 44 और नेशनल हाईवे 19 को अपग्रेड किया जाएगा. इसके ट्रैफिक जाम वाले रोड जोन पर फ्लाईओवर, ओवरब्रिज और अंडरपास का निर्माण होगा, ताकि ट्रैफिक एक जगह पर इकट्ठा न हो. फ्लाईओवर के लिए केंद्र और राज्य सरकार के साथ NHAI मिलकर काम करेगा. इस प्रोजेक्ट से दिल्ली-आगरा हाईवे पर रोड कनेक्टिविटी बेहतर होगी. इस रोड कॉरिडोर से रोजाना 70 हजार तक कारें गुजरती हैं, इसके साथ ही माल ढोने वाले भारी वाहनों का भी लोड रहता है. दिल्ली से आगरा-मथुरा जाने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या भी होती है.ऐसे में ट्रैफिक जाम टेंशन की वजह है.

गडकरी ने कहा कि रोड ओवर ब्रिज से रेलवे क्रॉसिंग पर गाड़ियों के ठहराव के साथ लगने वाला जाम खत्म होगा. अभी के पुल और सड़क, चौराहों पर ट्रैफिक जाम, भीड़भाड़ कम करने के लिए भी एक्शन प्लान तैयार होगा. फ्लाईओवर और अंडरपास के लिए रेड जोन वाले ट्रैफिक प्वाइंट को चुना जाएगा. साथ ही सर्विस लेन बनाकर लोकल और शहर के बाहर के ट्रैफिक को डायवर्ट किया जाएगा. दिल्ली-NCR और आगरा के बीच यात्रा के समय में काफी कमी आएगी.

यूपी चुनावः कांग्रेस ने मांगी 181 सीटें पर अखिलेश एक चौथाई भी देने के मूड में नहीं, सपा ने दिया जवाबी ऑफर

लखनऊः उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में कशमकश बढ़ती जा रही है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव के दावे की मानें तो कांग्रेस ने 181 सीटें मांगी हैं. वहीं सपा ने भी कांग्रेस के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए सिर्फ 36 सीटों का शुरुआती ऑफर दिया है. दरअसल, कांग्रेस ने कथित तौर पर सपा को जो 181 की सूची सौंपी है, उसमें से लगभग दो दर्जन सीटों पर सपा के सिटिंग विधायक हैं. वहीं अगर 2022 के विधानसभा चुनाव को आधार मानें तो कुल 46 सीटों पर कांग्रेस को 20 हजार से ज्यादा वोट मिले थे. 330 ऐसी सीटें हैं, जहां कांग्रेस को 5 हजार से भी कम



वोट मिले थे. जिन 46 सीटों पर कांग्रेस को 20 हजार से ज्यादा वोट मिले, उनमें से 10 ऐसी सीटें हैं, जिन पर सपा को जीत मिली थी. ऐसे में सपा सूत्रों का कहना है कि जायज तरीके से कांग्रेस का दावा अधिक से अधिक 36 सीटों पर बनता है.सपा और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर औपचारिक वार्ता जल्द शुरू होने वाली है.

सपा और कांग्रेस में सीट बंटवारे पर वार्ता

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में सपा-कांग्रेस गठबंधन का मुकाबला सीधे बीजेपी से है. कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में दमदार प्रदर्शन के बाद यूपी में फिर से अपनी जड़े जमाने की कोशिश में जुटी है. ऐसे में वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़कर अपना दमखम दिखाना चाहती है. खासकर अवध क्षेत्र में कानपुर, लखनऊ, रायबरेली-अमेठी से पूर्वांचल में प्रयागराज-वाराणसी जैसे क्षेत्रों में पार्टी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, ताकि 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए नींव तैयार की जा सके.

कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड निराशाजनक

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद जैसे नेता 150 से 170 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं. लेकिन 2022 के चुनावी आंकड़ों कुछ अलग ही हकीकत बयां करते हैं. यूपी की 330 सीटों में कांग्रेस 5-5 हजार वोट भी नहीं जुटा पाई थी.

'कृष्ण टेढ़े हैं...' वाले बयान के बाद पहली बार मथुरा जाएंगे बागेश्वर बाबा

नई दिल्ली। कुंडा की राम कथा से एक ऐसा ऐलान हुआ है, जिसने पूरे ब्रजमंडल से लेकर यूपी की सियासत तक हलचल मचा दी है. कथा के दूसरे दिन बाबा बागेश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने मंच से ही कह दिया- 21 नवंबर को हम बांके बिहारी के दर्शन करने जा रहे हैं. बस, क्या था... पंडाल में बैठी भीड़ ने तालियों और जयकारों से पूरा महल गूंजा दिया. हालांकि, बागेश्वर बाबा ने कहा कि बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के पीछे उनका मकसद किसी राजनीतिक पार्टी को लाभ दिलाना



नहीं है. धीरेंद्र शास्त्री ने अपने चिर-परिचित अंदाज में कहा, 'कृष्ण लला आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे.' ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक इशारा था. इशारा उस संकल्प का, जो अब मथुरा की गलियों से उठकर देशभर में गूंजने वाला है. धीरेंद्र शास्त्री ने साफ कहा, 'यादव में हम माधव को देखते हैं, माधव में यादव को देखते हैं. हमारे लिए न कोई जाति है, न कोई पात है, न कोई भेदभाव है. कथा का ध्येय ही यही है कि सब एक हों. हम बांके बिहारी जाकर ठाकुर जी के दर्शन करेंगे और वहीं से प्रण लेंगे कि मथुरा में औरंगजेब की निशानी का जो कलंक है, वो मिट जाए. हमारे कृष्ण कन्हैया भव्य रूप में, दिव्य रूप में वहां विराजमान हो जाएं.

कुंडा की कथा को लोग चुनावी कथा बता रहे हैं, इस पर बाबा बागेश्वर ने हंसते हुए जवाब दिया. बागेश्वर बाबा बोले, 'हम अपना काम करने निकले हैं, लोग अपना काम कर रहे हैं. कथा तो हमारी पांचों साल चलती है. अभी चुनाव का साल है, तो लोग इसे चुनाव से जोड़ेंगे ही. लेकिन हम साफ कह देते हैं, हम राम कथा चुनाव के लिए नहीं करते, हम कथा सनातन के लिए करते हैं. किसी को फायदा होता है, तो वो उसका ध्येय है. हमारा सिद्धांत बिल्कुल क्लियर कट है, सनातनियों को एकजुट करना. संविधान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 25 और 26 के अनुसार सबको अपने धर्म और परंपरा के प्रचार का पूरा हक है, कथा कहीं नहीं रोकी जा सकती.

खत्म हुई MP की टू-चाइल्ड पॉलिसी, सरकारी नौकरियों में अब नहीं लगेगी दो बच्चों की शर्त

भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर आ रही है. दरअसल मोहन यादव सरकार ने सरकारी नौकरियों और सेवाओं में लागू दो बच्चों की अनिवार्यता वाले नियम को खत्म कर दिया है. करीब 25 साल से लागू यह व्यवस्था अब समाप्त कर दी गई है. मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई विशेष कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई.



इसके बाद सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों या सेवा में कार्यरत कर्मचारियों पर तीसरी संतान होने की स्थिति में कोई कार्रवाई नहीं होगी. हालांकि, जिन कर्मचारियों को पहले ही सेवा से हटाया जा चुका है या जिन मामलों में अंतिम फैसला हो चुका है, उन्हें बहाल नहीं किया जाएगा.

गंगाजल यात्रा आस्था और सनातन परंपरा का प्रतीक : श्रीमहंत डॉ. रविंद्र पुरी

पशुपतिनाथ के जलाभिषेक को हरिद्वार से पांच हजार लीटर गंगाजल रवाना

23 नवंबर को नेपाल में भगवान शिव का होगा गंगाजल से अभिषेक, हर वर्ष निभाई जाती है परंपरा

के.के.पी संवाददाता

हरिद्वार। धर्मनगरी हरिद्वार की पवित्र गंगा से बुधवार को पांच हजार लीटर गंगाजल नेपाल स्थित प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर के लिए रवाना किया गया। गंगोत्री धाम से लाए गए गंगाजल की पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी स्थित मनसा देवी चरण पादुका मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई। इसके बाद संतों की मौजूदगी में गंगाजल यात्रा को नेपाल के लिए रवाना किया गया। 23 नवंबर को इसी गंगाजल से भगवान पशुपतिनाथ का जलाभिषेक किया जाएगा। गंगाजल यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं श्री मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष



श्रीमहंत डॉ. रविंद्रपुरी महाराज और गंगोत्री धाम के रावल शिवप्रकाश महाराज मौजूद रहे। चरण पादुका मंदिर में गंगाजल से भरे पात्रों की पूजा-अर्चना कर यात्रा की सफलता की कामना की गई। श्रीमहंत डॉ. रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि हरिद्वार और नेपाल के धार्मिक एवं आध्यात्मिक संबंध सदियों पुराने हैं। गंगाजल यात्रा इसी आस्था और सनातन परंपरा का प्रतीक है। हरिद्वार से रवाना हुआ गंगाजल नेपाल पहुंचकर भगवान पशुपतिनाथ के चरणों में अर्पित होगा। उन्होंने कहा कि गंगा और भगवान पशुपतिनाथ सनातन संस्कृति में आस्था के प्रमुख केंद्र हैं। यह यात्रा दोनों देशों के बीच धार्मिक और आध्यात्मिक संबंधों को और मजबूत करने का माध्यम है। गंगोत्री धाम के रावल शिवप्रकाश महाराज ने यात्रा की सफलता के लिए पूजा-अर्चना की। उन्होंने मां गंगा और भगवान पशुपतिनाथ से देश और समाज में सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की। धार्मिक मान्यता के अनुसार गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक करना पुण्यकारी माना जाता है। इसी परंपरा के तहत हर वर्ष हरिद्वार की पवित्र गंगा से गंगाजल नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर भेजा जाता है। नेपाल पहुंचने के बाद 23 नवंबर को विधि-विधान के साथ भगवान पशुपतिनाथ का जलाभिषेक किया जाएगा।

मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में दिव्य-भव्य होगा कुंभ : राजीव भट्ट

एचआरडीए सदस्य बनाए जाने पर धर्मशाला प्रबंधक सेवा समिति ने किया सम्मानित, कुंभ की तैयारियों और उत्तरी हरिद्वार की समस्याओं पर हुई चर्चा

के.के.पी संवाददाता

हरिद्वार। कुंभ मेले की तैयारियों के बीच उत्तरी हरिद्वार के विकास और धर्मशालाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर उम्मीदें बढ़ने लगी हैं। हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण (एचआरडीए) का सदस्य बनाए जाने पर राजीव भट्ट का हरिद्वार धर्मशाला प्रबंधक सेवा समिति ने स्वतंत्र पुरी धाम में भव्य स्वागत एवं सम्मान किया। इस दौरान आगामी कुंभ मेले को दिव्य-भव्य बनाने के साथ उत्तरी हरिद्वार में यातायात, पार्किंग, पेयजल,सार्वजनिक शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई।

राजीव भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में आगामी कुंभ



मेला दिव्य और भव्य होगा। कुंभ देश-विदेश के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। इसके सफल आयोजन के लिए सभी विभागों और सामाजिक संगठनों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। एचआरडीए सदस्य के रूप में वह क्षेत्र के विकास और धर्मशालाओं से जुड़ी समस्याओं को उचित मंच पर उठाने का प्रयास करेंगे। समिति के अध्यक्ष महंत भीमसेन ने कहा कि राजीव भट्ट को प्राधिकरण में जिम्मेदारी मिलने से उत्तरी हरिद्वार के विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। कुंभ से पहले क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाना प्राथमिकता होनी चाहिए। समिति के महामंत्री मनोज बिष्ट ने कहा कि उत्तरी हरिद्वार में बड़ी संख्या में धर्मशालाएं हैं, जहां कुंभ और अन्य धार्मिक पर्वों पर लाखों श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है। ऐसे में सड़क, बिजली, पानी, पार्किंग और सफाई जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राजीव भट्ट इन समस्याओं को प्राधिकरण के समक्ष प्रमुखता से रखेंगे।

कोषाध्यक्ष सोनू शर्मा ने कहा कि धर्मशालाएं हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं को ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कुंभ मेले को देखते हुए धर्मशालाओं से संबंधित व्यवस्थाओं और सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

एक नजर

जल संरक्षण में चम्पावत की धाक, राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतिम चरण तक पहुंचा जिला

केंद्रीय टीम ने तीन दिन तक परखे जल स्रोत पुनर्जीवन, झील और वर्षा जल संचयन के काम



के.के.पी संवाददाता/चम्पावत। सूखते जल स्रोतों को फिर से जीवित करने और बारिश के पानी को सहेजने की दिशा में चम्पावत जिले के प्रयास अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने की ओर हैं। जल शक्ति मंत्रालय के 7वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2026 के लिए जिले को अंतिम चरण के भौतिक सत्यापन के लिए चुना गया है। मंत्रालय की केंद्रीय टीम ने तीन दिनों तक जिले में जल संरक्षण कार्यों को जमीन पर जाकर परखा। दौरे के अंतिम दिन टीम ने लोहाघाट की अक्कल धारा के पुनर्जीवन कार्य देखे, जो सारा योजना के तहत प्रस्तावित हैं। इसके बाद कोलीढेक झील का निरीक्षण किया गया। पाटी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में छत के पानी को सहेजने के लिए बनाए गए रूफ वाटर हार्वेस्टिंग टैंक की गुणवत्ता भी जांची गई। भिंगराड़ा वन रेंज में कैम्पा और ग्रीन इंडिया मिशन के तहत किए गए वृक्षारोपण, चाल-खाल, गली प्लगिंग और चेकडैम जैसे कार्यों का भी अवलोकन किया गया। निरीक्षण के बाद केंद्रीय टीम ने जिले में जल संरक्षण के नवाचारों और कार्यों की गुणवत्ता की सराहना की। टीम ने जिला सारा सेंटर के उस समन्वय की भी तारीफ की, जिसके जरिए सिंचाई, पेयजल और वन विभाग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी अजय सिंह, खंड विकास अधिकारी लोहाघाट रविंद्र रावत सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

सरकारी पैंशनर्स संगठन ने वृहद आन्दोलन की दी चेतावनी

के.के.पी संवाददाता/भिकियासैण(अल्मोड़ा)। उत्तराखंड सरकारी पैंशनर्स संगठन ने 8वें वेतन आयोग को सरकार द्वारा भेजी गई ट्रम्स आफ रिफरैंश में पैशनर को शामिल नहीं किए जाने पर गहरी नारजगी संगठन की भिकियासैण में बैठक में जताई गयी। साथ ही एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में कहा है आठवें वेतन आयोग को भेजे गए ट्रम्स आफ रिफरैंश में शीघ्र पैशनर को शामिल नहीं किया गया तो देशभर में पैंशनर्स बड़े आन्दोलन चलाने के लिए बाध्य होंगे। बैठक को सम्बोधित करते बैठक में वक्ताओं ने कहा कि सरकार मध्यवर्गीय परिवारों को उजाड़ने में तूली हुई है। ठेकेदारी प्रथा शुरू कर पढ़ें लिखे नौजवानों को बंधुआ मजदूरी करने के लिए वाध्य कर रही है सरकारी कर्मचारियों की पैंशन बंद करने पर आमादा है जबकि यहां के अनेकों नेता आठ से दस बार तक की पैंशन ले रहे हैं।बैठक के अंत में संगठन के सक्रिय सदस्य भवानी दत्त रिखाड़ी व आनन्द प्रकाश लखचौरा के निधन पर शोक व्यक्त किया गया।यहां डीएस नेगी, तुला सिंह तड़ियाल,केएन कबडवाल, गुसाईं सिंह उनियाल, बचीराम आर्य, बाला दत्त उपाध्याय, गोपाल दत्त भगत, गंगा सिंह बिष्ट, एसपी सिंह राजौरिया, दीवान सिंह रावत, बहादुर रग सिंह रावत, नवीन जोशी, बाला दत्त कोटनाला, रमेशचंद्र सिंह बिष्ट, गोविन्द राम टम्टा, देवी दत्त लखचौरा, किसन सिंह, कमलनाथ, राजे सिंह आदि रहे।

रामलीला मैदान में भाजपा के बाद कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन

कुमारी शैलजा समेत दिग्गज नेताओं ने साधा धामी सरकार पर निशाना ; रैली के बीच टिकट बदलाव की मांग ने उजागर की पार्टी की अंदरूनी खींचतान

के.के.पी संवाददाता

लोहाघाट। विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के साथ लोहाघाट का ऐतिहासिक रामलीला मैदान सियासी शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बन गया है। दो दिन पहले भाजपा के पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल की रैली के बाद बुधवार को कांग्रेस विधायक खुशाल सिंह अधिकारी ने बड़ी रैली आयोजित कर अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया। रैली में उमड़ी भीड़ के बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी ने लोहाघाट की सियासत को नई चर्चा दे दी। हालांकि, रैली के दौरान ही टिकट बदलाव की मांग को लेकर उठे नारों ने कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान भी सामने ला दी।

रामलीला मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने कार्यकर्ताओं का आभार जताया। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तराखंड की जनता बदलाव के लिए तैयार है। अंकिता हत्याकांड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देवभूमि में



ऐसी घटनाएं पूरे प्रदेश को शर्मसार करती हैं। उन्होंने प्रदेश के करीब साढ़े तीन हजार स्कूलों में एक-एक शिक्षक होने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो शिक्षा समेत प्रदेश की व्यवस्थाओं में बदलाव किया जाएगा। उन्होंने विधायक खुशाल सिंह अधिकारी के प्रयासों की सराहना करते हुए कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी के विचारों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।

खटीमा विधायक एवं विधानसभा में कांग्रेस के उपनेता भुवन कापड़ी ने बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, जबकि बाहरी राज्यों के लोगों को ठेके और नौकरियों में अवसर मिल रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि प्रदेश में बदलाव की मांग उठ रही है। उन्होंने खुशाल सिंह अधिकारी के कार्यों की सराहना की।

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने जल, जंगल और जमीन के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि पर्वतीय क्षेत्रों की जमीन बाहरी लोगों को बेची



जा रही है। उन्होंने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए।

विधायक खुशाल सिंह अधिकारी ने कहा कि उनके पांच साल के कार्यकाल में जनता के हितों को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने रैली में पहुंचे लोगों को अपना समर्थक बताते हुए कहा कि ये वे लोग हैं जो हर सुख-दुख में उनके साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी राजनीति का आधार जनता का विश्वास है। सरयू पेयजल योजना को लेकर उन्होंने सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि योजना की डीपीआर तक स्वीकृत नहीं हुई है। इसके बावजूद योजना को स्वीकृत बताकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने अपने कार्यकाल में क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए किए गए प्रयासों का उल्लेख करते हुए समर्थकों का आभार जताया।

रैली का संचालन युवा नेता भुवन चौबे और प्रकाश मेहरा ने किया। इस दौरान पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा, पूर्व विधायक रंजीत रावत, हेमेश खर्कवाल, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विशाल भोजक, जिलाध्यक्ष चिराग फर्त्याल, मुन्ना सिंह ढेक, भगीरथ भट्ट, पूरन कठायत, पप्पू वर्मा समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

बॉक्सड्रैली के बीच टिकट बदलाव की मांग से गरमाई कांग्रेस की सियासत।

कांग्रेस की रैली में जहां विधायक खुशाल सिंह अधिकारी ने भीड़ जुटाकर अपनी ताकत दिखाई, वहीं पार्टी के भीतर टिकट को लेकर चल रही खींचतान भी खुलकर सामने आ गई। प्रदेश प्रभारी का काफिला चंपावत से लोहाघाट पहुंचने के दौरान मानेसर में कुछ कार्यकर्ताओं ने मुन्ना सिंह ढेक और युवा जिलाध्यक्ष चिराग फर्त्याल के समर्थन में नारेबाजी की। उन्होंने लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस टिकट बदलने की मांग उठाई। विधायक आवास के बाहर भी नारेबाजी कर विरोध जताया गया। रैली समाप्त होने के बाद भी इन कार्यकर्ताओं ने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के सामने अपना विरोध दर्ज कराया। इससे साफ हो गया कि 2027 के चुनाव से पहले लोहाघाट कांग्रेस में टिकट को लेकर दावेदारी और अंदरूनी खींचतान का दौर तेज हो गया है।

जनगणना प्रचार रथ को डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना



के.के.पी संवाददाता

अल्मोड़ा। जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत स्व-गणना प्रक्रिया के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर से जनगणना प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से जनगणना प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता करने की अपील की। उन्होंने कहा कि नागरिक स्व-गणना के माध्यम से अपने परिवार से संबंधित जानकारी स्वयं ऑनलाइन दर्ज करें। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में जनगणना के द्वितीय चरण के अंतर्गत 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक स्व-गणना की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस अवधि में नागरिक निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने परिवार की जानकारी सही एवं पूर्ण रूप से दर्ज कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि स्व-गणना की प्रक्रिया पूरी करने के बाद प्राप्त स्व-गणना आईडी को अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखें, क्योंकि आगे की जनगणना प्रक्रिया में इसकी आवश्यकता होगी। जनगणना निदेशालय, उत्तराखंड एवं भारत सरकार की ओर से प्रत्येक जनपद में जनगणना प्रचार रथ भेजे जा रहे हैं। यह प्रचार रथ जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर आमजन को ऑनलाइन पंजीकरण, स्व-गणना की प्रक्रिया तथा जनगणना में प्रत्येक नागरिक की सहभागिता के महत्व की जानकारी देगा। साथ ही लोगों को निर्धारित अवधि में स्व-गणना के लिए प्रेरित करेगा। प्रचार रथ के माध्यम से नागरिकों को स्व-गणना की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि अधिक से अधिक लोग स्वयं ऑनलाइन माध्यम से अपने परिवार का विवरण दर्ज कर जनगणना कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अनामिका सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

आंवला नवमी पर तीर्थ पुरोहितों ने किया पौधरोपण, सामूहिक खिचड़ी भोज में उमड़ी भीड़

रघुनाथ मंदिर में विधि-विधान से की आंवले के वृक्ष की पूजा, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

के.के.पी संवाददाता

हरिद्वार। आस्था, परंपरा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए आंवला नवमी के अवसर पर बुधवार को ज्वालापुर के पांडेवाला स्थित रघुनाथ मंदिर में तीर्थ पुरोहितों की ओर से सामूहिक खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों तीर्थ पुरोहितों ने आंवले के वृक्ष की विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की और प्रसाद ग्रहण किया। धार्मिक आयोजन के साथ ही तीर्थ पुरोहितों ने आंवले की पौध रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी लिया। इस अवसर पर तीर्थ पुरोहित अंशुल श्री कुंज ने कहा कि आंवला नवमी सनातन धर्म में विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखती है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने की परंपरा है। आंवले का वृक्ष धार्मिक आस्था के साथ-साथ स्वास्थ्य और पर्यावरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा



कि धार्मिक पर्व केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि इनके माध्यम से समाज को प्रकृति और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास कराना चाहिए। पौधरोपण कर उसकी नियमित देखभाल करना भी हम सभी का दायित्व है।

उन्होंने कहा कि सामूहिक खिचड़ी भोज जैसे आयोजन आपसी भाईचारे, सामाजिक समरसता और एकजुटता को मजबूत करते हैं। ऐसे आयोजनों से नई पीढ़ी को अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ने का अवसर मिलता है। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा, शशिकांत वशिष्ठ, सचिन कौशिक, अशोक त्रिपाठी, रमेश सिखौला, प्रेम त्रिपाठी, प्रवीण शर्मा, वैभव शिवपुरी, उमाशंकर वशिष्ठ, भोमेश श्री कुंज, श्रीराम सरदार, मधुसूदन प्रधान, तरित, आदित्य वशिष्ठ, मोहित पालीवाल, पंकज उपाध्याय, राजीव झा, संतोष गौतम, पंकज अधिकारी, मनीष पाराशर और महेश तुम्बड़िया सहित बड़ी संख्या में तीर्थ पुरोहित मौजूद रहे।

भूस्खलन से लड़ाई में उत्तराखण्ड बनेगा ओडिशा का मददगार

के.के.पी संवाददाता

प्राकृतिक आपदाएं सीमाओं और भौगोलिक दायरों में बंधकर नहीं आतीं। इनके प्रभाव अलग-अलग राज्यों में भले ही अलग स्वरूप में दिखाई दें, लेकिन इनसे निपटने की चुनौतियां और समाधान कई बार एक जैसे होते हैं। उत्तराखण्ड और ओडिशा के बीच भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन को लेकर प्रस्तावित सहयोग इसी सोच का महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह पहल केवल दो राज्यों के बीच प्रशासनिक समझौता नहीं, बल्कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में ज्ञान, अनुभव और वैज्ञानिक तकनीक साझा करने की दिशा में एक सार्थक कदम है। उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियां उसे भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति बेहद संवेदनशील बनाती हैं। पहाड़ों में लगातार हो रहे निर्माण कार्य, अनियोजित विकास, सड़क चौड़ीकरण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक असंतुलन ने भूस्खलन के खतरे को और गंभीर बनाया है। ऐसे में राज्य के सामने चुनौती केवल आपदा के बाद राहत और बचाव तक सीमित नहीं है, बल्कि आपदा आने से पहले जोखिम को पहचानना और संभावित नुकसान को न्यूनतम करना भी है।

दूसरी ओर, ओडिशा में चक्रवात और बाढ़ जैसी आपदाएं लंबे समय से बड़ी चुनौती रही हैं। हालिया बाढ़ के बाद गंजाम, गजपति, कंधमाल और रायगड़ा जिलों में भूस्खलन की नई चुनौती सामने आना इस बात का संकेत है कि बदलती प्राकृतिक परिस्थितियों में आपदाओं का स्वरूप भी बदल रहा है। अब किसी राज्य की आपदा प्रबंधन रणनीति को केवल पारंपरिक अनुभवों तक सीमित रखना पर्याप्त नहीं होगा। उत्तराखण्ड ने भूस्खलन के जोखिम का वैज्ञानिक आकलन, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, निगरानी, पूर्व चेतावनी, उपग्रह तकनीक और भौगोलिक सूचना प्रणाली के इस्तेमाल की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र (यूएलएमएमसी) की स्थापना भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। जमीन के भीतर की संरचना को समझने से लेकर भूस्खलन के मलबे से उत्पन्न संभावित खतरों के आकलन तक आधुनिक तकनीक का उपयोग भविष्य की सुरक्षा के लिए जरूरी है। प्रस्तावित एमओयू के माध्यम से इन अनुभवों को ओडिशा तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा। लेकिन इस सहयोग की असली सफलता समझौते पर हस्ताक्षर करने से नहीं, बल्कि उसके धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन से तय होगी। विशेषज्ञों का नियमित आदान-प्रदान, संयुक्त वैज्ञानिक अध्ययन, प्रशिक्षण, तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता और स्थानीय स्तर पर चेतावनी तंत्र विकसित करना इसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपदा प्रबंधन को सरकारी बैठकों और कागजी योजनाओं से बाहर निकालकर आम नागरिकों की सुरक्षा से जोड़ना होगा। पहाड़ों में रहने वाले लोगों से लेकर ओडिशा के आपदा प्रभावित क्षेत्रों तक स्थानीय समुदायों को प्रशिक्षित करना और उन्हें समय रहते चेतावनी उपलब्ध कराना अनिवार्य है। उत्तराखण्ड और ओडिशा की यह पहल अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण बन सकती है। आपदा से लड़ाई प्रतिस्पर्धा से नहीं, बल्कि सामूहिक अनुभव और साझा प्रयासों से जीती जा सकती है।

यदि यह सहयोग ठोस परिणामों में बदलता है तो उत्तराखण्ड का पहाड़ी अनुभव ओडिशा के लिए सुरक्षा कवच बनेगा और देश में आपदा प्रबंधन की एक नई साझेदारी का रास्ता खोलेगा।लोहाघाट में कांग्रेस की रैली में उमड़ा जनसैलाब, खुशाल अधिकारी ने दिखाई ताकत

संस्कृति विभाग ने चार साल से नहीं किया है मानदेय भुगतान

के.के.पी संवाददाता

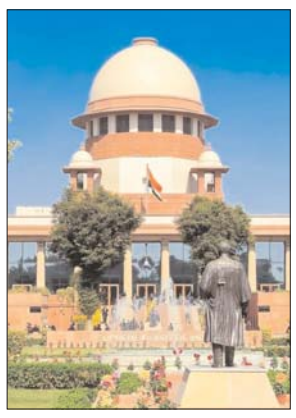
अल्मोड़ा। लोक कलाकार महासंघ ने सरकार और संस्कृति विभाग पर लोक कलाकारों का शोषण करने का आरोप लगाया है। कहा साल साल बाद भी उनके मानदेय बिलों का भुगतान नहीं हुआ है। संगठन ने 10 दिन के भीतर समस्याओं का समाधान नहीं होने पर प्रदेश में आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है।लोक कलाकार महासंघ अध्यक्ष सुंदर लटवाल ने प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में सरकार और संस्कृति विभाग पर कलाकारों के साथ वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा संस्कृति विभाग में राज्य के अलग-अलग जिलों में करीब 400 सांस्कृतिक दल पंजीकृत हैं। विभाग द्वारा इन सांस्कृतिक दलों को सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु कार्यक्रम दिए गए। आरोप लगाया विभाग ने 4 साल बाद भी बिलों का भुगतान नहीं किया है। कहा करीब डेढ़ करोड़



रूपया बकाए केभगतान के लिए वह मुख्यमंत्री से लेकर विभागीय अधिकारियोंक पास जाकर शिकायत दर्ज कर चुके हैं। सकारात्मक आश्वासन के बाद भी समस्या हल नहीं हुई। उन्होंने आरटीआई के हवाले से बताया वर्ष 2025 -26 में विभाग ने सांस्कृतिक दलों पर 4,86, 12,281 रु खर्च होने की जानकारी दी है। जब 4 साल से करोड़ों रुपया बकाया है तो विभाग को बताना चाहिए उसने यह धनराशि कहां खर्च की है। श्री लटवाल ने कहा सांस्कृतिक दलों को प्रति कार्यक्रम बहुत कम मानदेय और वाहन भत्ता मिलता है। इसके बावजूद भी विभाग भुगतान बिलों से 18 फीसदी जीएसटी की कटौती कर रहा है, जबकि सूचना और लोक संपर्क विभाग किसी प्रकार की कटौती नहीं करता। राज्य सरकार के दो विभागों के अलग-अलग नियम सरकार की नीति पर सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने कहा 70 के दशक से पंजीकृत लोक कलाकार और सांस्कृतिक दल संस्कृति के संवर्धन का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनके कल्याण की कोई स्पष्ट योजना नहीं बनाई है। लोक कलाकार संघ ने प्रदेश के कला साधक सम्मान और तिलू रौतेली आदि पुरस्कारों के चयन में वरिष्ठ लोक कलाकारों को स्थान देने, वरिष्ठ लोक कलाकारों को सम्मानजनक पेंशन लागू करने, नॉर्थ जोन की तरह मानदेय देने और समय पर भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग उठाई। संगठन ने 10 दिन के भीतर समस्याओं का समाधान नहीं होने पर जिला मुख्यालयों में संस्कृति विभाग से संबंधित कार्यालय में प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। पत्रकार वार्ता में वरिष्ठ रंगकर्मी कृष्ण मोहन नंदा, रमेश लाल, शीला पंत, पूरन बिष्ट, नीरज कुमार, अमित भट्ट, विनोद आर्य मौजूद थे।

जजों की नियुक्ति प्रक्रिया तय करने वाले मेमोरेंडम को अंतिम रूप देने की मांग

सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस



नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया तय करने वाले मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) को अंतिम रूप देने की मांग पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी हुआ है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल से भी जवाब मांगा है. याचिका में 11 साल से मेमोरेंडम का प्रोसीजर तैयार न होने का मसला उठाया गया है.

एनजीओ लोक प्रहरी की याचिका में कहा गया है कि जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ख्वाक को अंतिम रूप देना जरूरी है. याचिका में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) और केंद्र सरकार को ख्वाक में जरूरी बदलाव कर इसे जल्द अंतिम रूप देने का निर्देश देने की मांग की गई है. साथ ही कॉलेजियम के फैसलों को सूचना के अधिकार (RTI) कानून के दायरे में लाने की मांग भी की गई है.

सुप्रीम कोर्ट के जजों के वरिष्ठता क्रम में चौथे नंबर पर आने वाले जस्टिस सुंदरेश ने सुनवाई की शुरुआत में कहा कि वह खुद कॉलेजियम का हिस्सा हैं. ऐसे में क्या उन्हें इस मामले को सुनना चाहिए? इसका जवाब देते हुए याचिकाकर्ता के लिए पेश वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने कहा कि उन्हें सुनवाई से अलग होने की कोई ज़रूरत नहीं है. इसके बाद कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया.

दरअसल, 1999 में तैयार ख्वाक में कॉलेजियम व्यवस्था के तहत जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया तय की गई थी. 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) कानून रद्द करते हुए कॉलेजियम व्यवस्था बरकरार रखी थी. साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए सुझाव मांगे थे.

16 दिसंबर 2015 को कोर्ट ने MoP में बदलाव का काम केंद्र सरकार को सौंपा था. केंद्र और कॉलेजियम के बीच सहमति नहीं बनने के कारण यह प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है. याचिका में मांग की गई है कि CJI जरूरी बदलाव करें और कानून मंत्रालय एक महीने के भीतर MoP को अंतिम रूप दे.

ट्रंप पहुंचे चीन, प्रोटोकॉल तोड़कर पहुंचे जिनपिंग..., महाशक्तियों की बैठक पर टिकी दुनिया की नजर



नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौर पर पहुंचे, जहां पर उनका शानदार स्वागत किया गया है. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग प्रोटोकॉल तोड़कर खुद उन्हें रिसीव करने पहुंच गए और दोनों एक दूसरे के गले लगे. राष्ट्रपति ट्रंप का ये दौरा का महत्वपूर्ण माना जा रहा है. राष्ट्रपति ट्रंप यहां पर चीन और रूस के अपने समकक्षीय राष्ट्रपति शी जिनपिंग राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शेनझेन में बैठक में शामिल होंगे.

इस बैठक में ईरान संघर्ष और यूक्रेन युद्ध जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है. ट्रंप आसियान शिखर सम्मेलन और क्वाड नेताओं की बैठक में शामिल होने के लिए फिलीपींस पहुंचे हुए थे.

ट्रंप ने चीन निकलने से पहले ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर लिखा था कि मैं अब फिलीपींस से चीन जा रहा हूं. फिलीपींस में हमारी बिजनेस, नेशनल सिक्योरिटी और अन्य विषयों पर बहुत अच्छी बातचीत हुई. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने फिलीपींस के साथ एक नई और बिल्कुल अलग बिजनेस डील की है. यह एक ऐतिहासिक समझौता होगा, जो खासतौर पर हमारे किसानों और एनर्जी सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को क्वाड देशों के बीच बढ़ते सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि ये देश एक स्वतंत्र, खुले, स्थिर और समृद्ध इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. मनीला में आयोजित क्वाड लीडर्स समिट को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'क्वाड' को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारियों में से एक बताया.

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शेनझेन में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) फोरम के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की. इस बैठक में पुतिन ने शी से कहा कि रूस और चीन को मिलकर एक अधिक निष्पक्ष दुनिया बनाने की दिशा में काम करना चाहिए.

हमारे और चीन के बीच संबंध स्थिर हैं. हमारे रिश्ते सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. इसके अलावा शी ने कहा कि हमें एक बड़ी शक्ति के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को मजबूती से निभाना चाहिए.

रूस और चीन को हर क्षेत्र में अपना सहयोग और गहरा करना चाहिए. उन्होंने कहा, 'हमारे संबंधों ने इस उथल-पुथल भरी दुनिया में अधिक स्थिरता पहुंचाई है.' उन्होंने रूस-चीन संबंधों को समानता, आपसी सम्मान और दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद सहयोग का एक सही उदाहरण करार दिया.

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का पहला रूट तैयार, सूरत से बिलिमोरा सेक्शन में 20 नवंबर से दौड़ेगा हाईवोल्टेज पावर

मुंबई। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के सूरत से बिलिमोरा रूट पर 20 नवंबर से बिजली दौड़ने लगेगी. इस दिन ओवरहेड इक्विपमेंट (OHE) सिस्टम को हाई पॉवर वाली बिजली लाइनों से जोड़ा जाना अगले साल 15 अगस्त से बुलेट ट्रेन चलाने की दिशा में बड़ा कदम होगा. इसके लिए 2X25 KV ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम से लैस किया जा रहा है.सूरत और बिलिमोरा के बीच 50 किमी लंबे एलिवेटेड रूट पर अप डाउन दोनों लाइनें तैयार हो गई हैं. बुलेट ट्रेन पूरी तरह से 2029 तक शुरू करने का लक्ष्य है. इस बुलेट ट्रेन रूट में 14 सबस्टेशन बनाए गए हैं, जो 508 किमी लंबे कॉरिडोर के स्ट्रैटजिक लोकेशन पर होंगे, ताकि पूरे रूट को बेरोकटोक बिजली मिल सके. ये सबस्टेशन ग्रिड से बिजली लेकर ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम तक पहुंचाएंगे. इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की निगरानी कंट्रोल रूम भी बनाया गया है. ओवरहेड इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बिजली लाइन चालू होने के बाद ट्रायल आदि का कार्य आगे बढ़ेगा. मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के गुजरात के सूरत-बिलिमोरा सेक्शन को हाई वोल्टेज बिजली से चार्ज करने की तैयारी है. 508 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में यह पहला ऐसा सेक्शन होगा, जहां ओवरहेड तारों में हाई वोल्टेज बिजली दौड़ाई जाएगी. इस हाई स्पीड कॉरिडोर के विद्युतीकरण के लिए भारत में पहली बार जापानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है. बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के बिजली नेटवर्क को मदद देने के लिए लगभग 22 हजार स्टील के खंभे लगाए गए हैं. इनकी ऊंचाई 3-4 मंजिला इमारत यानी करीब 10.5 से 14.5 मीटर ऊंचे हैं. डिपो सेक्शन समेत पूरे ट्रैक में 25700 से अधिक केंटिलीवर असेंबल किए गए हैं. भारत में पहली बार इस तकनीक के जरिये ओवरहेड तारों को बेहद सटीक मैकेनिकल तकनीक से इंस्टाल किया गया है. इससे बुलेट ट्रेन जब 320 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी तो उसका आगे का हिस्सा बिना किसी दिक्कत, शार्ट सर्किट या हाई-लो पॉवर के आसानी से हाईवोल्टेज बिजली सप्लाई कर सकेगा. बुलेट ट्रेन को लगातार बिजली सप्लाई के लिए गुजरात और महाराष्ट्र में मजबूत ग्रिड बनाया गया है. गुजरात में बिजली आपूर्ति के लिए गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के 220 केवी अंबेथा ग्रिड सबस्टेशन से की जाएगी.

ईरान की अमेरिकी नौसेना के दो अधिकारियों को धमकी.....ढूंढ लेंगे तुम्हें

दूतावास ने सोशल मीडिया पर दोनों अधिकारियों की तस्वीरें साझा कीं, पुराने आरोपों वाली पोस्ट को फिर से किया शेयर

तेहरान। ईरान ने अमेरिकी नौसेना के दो वरिष्ठ अधिकारियों को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए धमकी दी है। दक्षिण अफ्रीका स्थित ईरानी दूतावास ने अमेरिकी नौसेना के अधिकारियों की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा- 'वी विल फाइंड यू' यानी 'हम तुम्हें ढूंढ लेंगे'। यह धमकी अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस स्प्रूवंस के करीब 357 दिनों की तैनाती के बाद कैलिफोर्निया के सैन डिएगो स्थित नौसैनिक अड्डे पर लौटने के बाद सामने आई है।

ईरानी दूतावास ने जिन अधिकारियों को निशाने पर रखने की बात कही है, उनमें यूएसएस स्प्रूवंस के कमांडिंग ऑफिसर कमांडर लेह आर. टेट और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर जेफरी ई. यॉर्क शामिल हैं। दूतावास ने दोनों की तस्वीरों वाली अपनी पुरानी पोस्ट को दोबारा साझा करते हुए उसके साथ केवल 'वी विल फाइंड यू' लिखा। दूतावास ने इससे पहले 28 मार्च 2026 को भी दोनों अधिकारियों की तस्वीरें साझा की थीं। उस समय उसने आरोप लगाया था कि दोनों अधिकारियों ने ईरान के मिनाब शहर में एक प्राथमिक स्कूल पर तीन बार टॉमहॉक मिसाइल दागने का आदेश दिया था। ईरानी दूतावास के अनुसार, इस हमले में 168 बच्चों की मौत हुई थी। हालांकि, बच्चों की मौत और इसमें दोनों अधिकारियों की कथित भूमिका को लेकर ये ईरानी दूतावास के आरोप हैं।

यूएसएस स्प्रूवंस 21 नवंबर 2025 को मिशन पर रवाना हुआ था और 13 नवंबर 2026 को सैन डिएगो लौटा। अमेरिकी नौसेना के मुताबिक, करीब 357 दिनों की यह तैनाती द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी अमेरिकी डिस्ट्रॉयर की सबसे लंबी तैनाती रही। इस दौरान युद्धपोत ने अमेरिकी नौसेना के तीसरे, पांचवें और सातवें बेड़े के क्षेत्रों में काम किया तथा ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान में भी भूमिका निभाई।

ईरान की धमकी ऐसे समय आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को कड़ी चेतावनी दी है।

Sahara Refund: 47 लाख लोगों के खाते में आए 10 हजार करोड़



नई दिल्ली। अगर आपका पैसा भी सहारा इंडिया में फंसा हुआ है, तो आपके लिए अच्छी खबर है. सहारा इंडिया के निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलने लगा है. अब तक 47 लाख से ज्यादा निवेशकों के बैंक खातों में 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम भेजी जा चुकी है. खास बात यह है कि पिछले सात दिनों में ही 221.45 करोड़ रुपये जमाकर्ताओं के खातों में ट्रांसफर किए गए हैं.

सहारा रिफंड पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक, अब तक करीब 1.51 करोड़ लोगों ने अपना पैसा वापस पाने के लिए आवेदन किया है. इनमें से 47 लाख से ज्यादा निवेशकों को कुल 10,037.47 करोड़ रुपये का रिफंड दिया जा चुका है. इससे उन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनकी मेहनत की कमाई लंबे समय से सहारा की अलग-अलग सहकारी समितियों में फंसी हुई है.

आपका पैसा वापस पाने के लिए क्या करना होगा?

अगर आपने अभी तक रिफंड के लिए आवेदन नहीं किया है, तो इसके लिए केंद्र सरकार के CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल (https://mocrefund.crcs.gov.in/depositor/#/home) पर जाना होगा. वहां जमाकर्ता को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और जरूरी जानकारी भरनी होगी. आवेदन के लिए आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, आधार से लिंक बैंक खाता और जमा राशि से जुड़े दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है. आवेदन करते समय सभी जानकारियां सही भरना जरूरी है, ताकि वेरिफिकेशन में परेशानी न हो.

कैसे चेक करें रिफंड का स्टेटस?

रिफंड के लिए आवेदन करने के बाद निवेशक पोर्टल पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं. अगर आवेदन में कोई कमी या दस्तावेज से जुड़ी समस्या है, तो उसे ठीक करने की जरूरत हो सकती है. ध्यान रखें कि रिफंड की रकम आवेदन और दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के बाद ही जारी की जाती है. इसके अलावा, निवेशकों की सुविधा के लिए सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर तीन नए हेल्पलाइन नंबर 011-44716198, 011-44716498 और 011-44716887 भी जारी किए गए हैं.

आंखों में सनग्लासेस, हाथ में सिगरेट... मौत की अफवाहों के बीच किम जोंग का वीडियो, बेटी के साथ स्की करते आए नजर



नई दिल्ली। उत्तर कोरिया के तानाशाह नेता किम जोंग उन को लेकर कुछ समय पहले सोशल मीडिया और इंटरनेट पर उनकी मौत को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं. हालांकि बाद में उत्तर कोरिया ने उनकी तस्वीरें जारी कर इन दावों को खारिज कर दिया था. अब इन अटकलों पर पूरी तरह विराम लगाते हुए किम जोंग उन का एक वीडियो सामने आया है. खास बात यह है कि मौत की अफवाहों के बाद यह पहला मौका है जब किम को वीडियो में सार्वजनिक रूप से देखा गया है.

उत्तर कोरिया के सरकारी प्रसारक KCTV ने किम जोंग उन के एक निर्माणाधीन स्की रिजॉर्ट के दौरे का वीडियो जारी किया है. यह रिजॉर्ट देश के उत्तरी हिस्से में स्थित रयांगगांग प्रांत के समजियॉन पर्यटन क्षेत्र में तैयार किया जा रहा है. वीडियो और तस्वीरों में किम काफी सहज और खुश नजर आ रहे हैं.

मंगलवार को जारी तस्वीरों में किम जोंग उन एक कुर्सी पर बैठे दिखाई देते हैं. उनके हाथ में सिगरेट है, आंखों पर धूप का चश्मा लगा है और चेहरे पर मुस्कान साफ देखी जा सकती है. उनके पीछे उनकी पत्नी री सोल जू खड़ी नजर आती हैं. उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी KCNA के अनुसार, किम अपने परिवार और सत्तारूढ़ पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रविवार और सोमवार को चीन सीमा के नजदीक स्थित इस पर्यटन क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे थे.

दौरे के दौरान किम ने स्की सेंटर, होटल और अन्य सुविधाओं का जायजा लिया. सरकारी मीडिया के मुताबिक उन्होंने निर्माण कार्य की तारीफ करते हुए कहा कि सभी इमारतें बेहद शानदार ढंग से बनाई गई हैं और उनकी गुणवत्ता बेहतरीन है. रिपोर्ट में कहा गया कि इलाके की खूबसूरत वादियों और मनमोहक नजारों को देखकर किम काफी खुश हुए.

गोरखपुर में अखिलेश यादव का मेगा रोड शो, बीजेपी के गढ़ में सपा ने दिखाया दमखम



नई दिल्लीः समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव आज गोरखपुर में रोड शो किया. यह विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ अखिलेश यादव था. उनका रोड शो करीब 20 किमी लंबा रहा. उन्होंने गोरखपुर के चौरीचौरा क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद बाबू बंधू सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया और एक जनसभा को संबोधित किया.

अखिलेश यादव का गोरखपुर एयरपोर्ट से देवकही तक प्रस्तावित रोड शो जिले के तीन विधानसभा सीटों गोरखपुर सदर, गोरखपुर ग्रामीण और चौरीचौरा विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरा. ये तीनों विधानसभा सभा सीटें इस समय बीजेपी के कब्जे में हैं.अखिलेश यादव ने इस रोड शो के जरिए गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में सपा कार्यकर्ताओं में जोशभर कर उन्हें एकजुट करने और चुनाव की तैयारियों में जुट जाने के लिए प्रेरित किया. देवकही में आयोजित कार्यक्रम के बाद उनका गोरखपुर के धर्मशाला बाजार स्थित तिवारी हाता जाने का भी कार्यक्रम है.यह एक समय यूपी में माफिया की छवि रखने वाले बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी का आवास है. उन्हें पूर्वांचल का बड़ा ब्राह्मण नेता माना जाता था. उनके निधन के बाद उनके बेटों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली थी. सपा ने उन्हें चुनाव भी लड़ाया लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली. विधानसभा चुनाव से पहले सपा की नजर प्रदेश के ब्राह्मण वोटों पर है. माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण योगी आदित्यनाथ की सरकार से नाराज हैं. सपा प्रमुख इसी नाराजगी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं.

जिस चौरीचौरा में अखिलेश यादव जा रहे हैं, उसका स्वतंत्रता संग्राम में विशेष योगदान है. वहां के किसानों ने आजादी की लड़ाई के दौरान चार फरवरी, 1922 को चौरीचौरा पुलिस थाने में आग लगा दी थी. वो अंग्रेजों के साथ-साथ स्थानीय जमींदारों से परेशान थे.इस घटना में 19 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी. इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने 1920 में शुरू किया अपना 'असहयोग आंदोलन' को वापस ले लिया था. अगर हम गोरखपुर के राजनीतिक महत्व की बात करें तो इस शहर ने प्रदेश को दो मुख्यमंत्री दिए हैं. यह शुरू से ही बीजेपी का गढ़ रहा है. पिछले तीन चुनावों में बीजेपी ने इस जिले में शानदार प्रदर्शन किया है. साल 2022 के चुनाव में उसने सभी नौ सीटों पर जीत दर्ज की थी. वहीं 2017 में उसे 9 में से आठ और 2012 में नौ में से तीन सीटें अपने नाम की थी.

टोल पार करते ही इंश्योरेंस की चेतावनी, एनएचएआई का नया सिस्टम शुरू

नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने वाहनों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की वैधता सुनिश्चित करने के लिए अभिनव प्रणाली शुरू की है। इस नई व्यवस्था के तहत, अब टोल प्लाजा पार करते ही वाहन मालिकों को अपने इंश्योरेंस स्टेटस से जुड़ा एक एसएमएस प्राप्त हो सकता है। अगर आपके वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस समाप्त हो गया है या आपने इंश्योरेंस नहीं कराया है, तब यह एसएमएस आपको सूचित करेगा। यह पहल फिलहाल दिल्ली के अर्बन एक्सटेंशन रोड-टू (यूईआर-टू) पर स्थित मुंडका टोल प्लाजा पर एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई है, इस जल्द ही देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू करने की योजना है। यह सिस्टम टोल प्लाजा और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) के वाहन डेटाबेस के बीच डेटा साझाकरण पर आधारित है। जैसे ही कोई वाहन टोल प्लाजा से गुजरेगा, उसकी जानकारी तत्काल वाहन डेटाबेस को भेजी जाएगी। सिस्टम स्वचालित रूप से वाहन के इंश्योरेंस की वैधता की जांच करेगा। यदि जांच में पता चलता है कि वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वैध नहीं है, तब वाहन मालिक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर तुरंत एक एसएमएस भेजा जाएगा। इस मैसेज में वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, टोल प्लाजा पार करने का समय और इंश्योरेंस की समाप्ति तिथि जैसी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होगी, साथ ही इंश्योरेंस को तत्काल नवीनीकृत कराने की सलाह भी दी जाएगी। एनएचएआई का यह कदम वाहन चालकों को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अनिवार्य थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को समय पर रिन्यू कराने के लिए सचेत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एनएचएआई के अधिकारियों के अनुसार, यह एक रिमाइंडर नोटिफिक्केशन का काम करेगा, जिससे वाहन मालिक संभावित भारी जुर्माने से बच सकें। भारत में बिना वैध थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के वाहन चलाना कानूनन अपराध है।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति सीमा घटी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोहरे के कारण होने वाले सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य के पांच प्रमुख एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा कम की है। उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा विभाग ने कम दृश्यता को देखकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य कोहरे की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना है।

विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह शीतकालीन गति सीमा 15 नवंबर, 2026 से लेकर 15 फरवरी, 2027 तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि के दौरान, सुबह 08:00 बजे से रात 08:00 बजे तक नई नियम लागू रहने वाले है। इसके तहत, कारों के लिए अधिकतम गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है, जबकि यात्री बसों के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा और मालवाहक ट्रकों के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित किया गया है।

जिन पांच एक्सप्रेसवे पर नियम लागू, उसमें आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे शामिल हैं। यह कदम कोहरे के कारण होने वाले गंभीर हादसों को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिनमें अक्सर कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। गति सीमा कम होने से चालकों को आपात स्थिति में वाहनों को नियंत्रित करने और दुर्घटनाओं के प्रभाव को कम करने में सहायता मिलेगी। उत्तर प्रदेश यातायात निदेशालय ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे ठंड और कोहरे के मौसम में सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित गति सीमा का कड़ाई से पालन करें।

केक काटकर एमएस धोनी ने सेलिब्रेट की रिटायरमेंट, सामने आई तस्वीर

चेन्नई। चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज एमएस धोनी ने मंगलवार, 17 नवंबर को आईपीएल से संन्यास ले लिया. माही ने 45 साल की उम्र में आईपीएल को अलविदा कहा. सभी जानते हैं कि धोनी का चेन्नई सुपर किंग्स से एक खास रिश्ता है. फ्रेंचाइजी भी किसी भी हाल में धोनी को नहीं छोड़ना चाहती है. ऐसे में संन्यास के बाद भी धोनी चेन्नई के साथ बने रहेंगे. वह आईपीएल 2027 में मेंटॉर की भूमिका में दिखेंगे. धोनी संन्यास लेने के बाद इमोशनल हुए थे. उन्होंने सोशल मीडिया पर चेन्नई के साथ अपने



सफर का एक वीडियो शेयर किया था, लेकिन बुधवार, 18 अक्टूबर को उन्होंने केक काटकर अपनी रिटायरमेंट का सेलिब्रेशन किया.

एमएस धोनी ने अपने खास दोस्तों के साथ रिटायरमेंट केक काटा. केक पर लिखा है, 'थैंक्यू माही भैया. हमें इतनी सारी खुशियां देने के लिए. ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे.' चेन्नई सुपर किंग्स ने धोनी के केक काटते हुए का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है. वीडियो में धोनी अपने दोस्तों के साथ हैं. वह केक काटने के बाद सभी को केक खिलाते हैं, और कहते हैं कि मुझे तुम सभी मत खिलाना.

माही के फैंस को और चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस को यह वीडियो काफी पसंद आ रहा है. देखते ही देखते यह वीडियो और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं.

स्वामी/ प्रकाशक / मुद्रक
प्रमोद कुमार ने जय माँ गंगा प्रिंटर्स, हरिद्वार से मुद्रित कराकर कार्तिकेय कॉलोनी, फेस-3, दर्पण स्कूल वाली गली, निकट हनुमान मंदिर, कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी जनपद-नैनीताल (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित किया।
सम्पादक
प्रमोद कुमार
मो.7830201066
सह-सम्पादक
दया जोशी
मो.9412135616